▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/– रू.

श्रावण–भाद्रपद 2081, अगस्त 2024

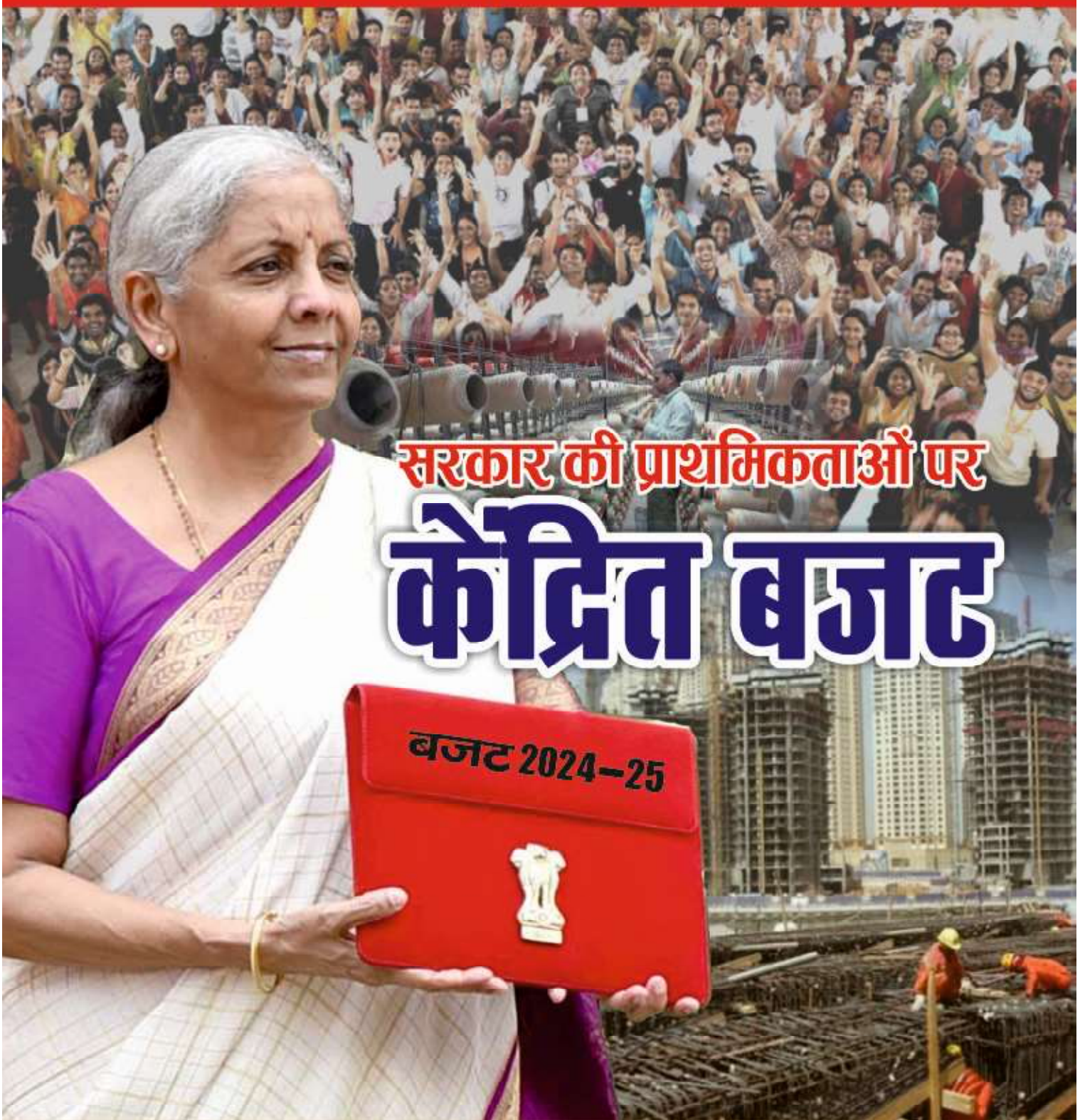

स्वदेशी पत्रिका और स्वदेशी परिवार की ओर से
स्वदेशी के सभी पाठकों, लेखकों तथा स्वदेशी में योगदानकर्त्ता को

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Swavlamban Bharat Abhiyan, Meetings

भोपाल, म.प्र.

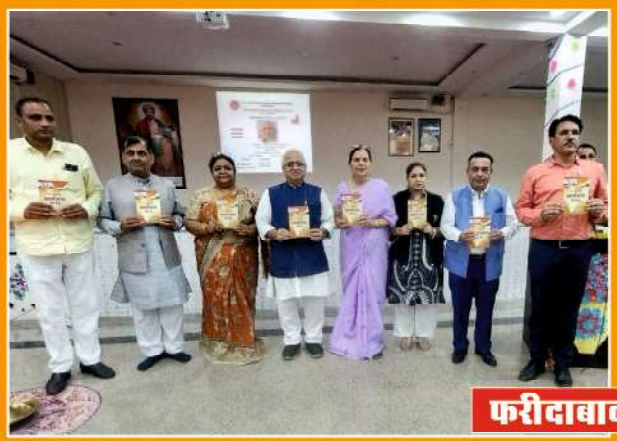

फरीदाबाद, हरियाणा

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–32, अंक–8
श्रावण–भाद्रपद 2081 अगस्त 2024

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

सरकार की प्राथमिकताओं पर केंद्रित बजट

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 बजट 2024–25
हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि
..... डॉ. धनपतराम अग्रवाल

11 बजट 2024–25
कदम–दर–कदमः देश विकास के पथ पर अग्रसर
..... अनिल तिवारी

13 बजट 2024–25
बजट की सकारात्मक दिशा
..... अनिल जवलेकर

15 बजट 2024–25
समावेशी विकास पर सरकार का जोर
..... शिवनंदन लाल

17 बजट 2024–25
आर्थिक विकास को गति देने वाला बजट
..... प्रहलाद सबनानी

19 बजट 2024–25
बजट में कृषि और ग्रामीण विकास
..... डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह

21 बजट 2024–25
बजट और मध्यम वर्ग
..... स्वदेशी संवाद

23 विमर्श
धुएं में बर्बाद होता भारत का भविष्य
..... विक्रम उपाध्याय

25 कृषि
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी प्राकृतिक खेती
..... देविन्दर शर्मा

27 आजकल
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तनः भारत की चिंता
..... विनोद जौहरी

29 जल प्रबंधन
पानी के लिए पर्याप्त प्रावधान है बजट में
..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

31 बैंकिंग
बैंकों में घटता चालू और बचत खाता अनुपात, चिंतन का विषय
..... विकास सिन्हा

पाठकनामा

भारत के पास कपड़ा निर्यात बढ़ाने का अवसर

बांग्लादेश में अस्थिरता और अराजकता के कारण वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। सैकड़ों लोगों की मौत के बाद अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई है। लेकिन हिंसा और तोड़–फोड़ की वजह से बांग्लादेश के रेडीमेट कपड़ा व्यापारियों के एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने सभी व्यापारियों को अनिश्चितकाल तक फैक्ट्रियां बंद रखने को कहा है। जिसकी वजह से अन्य देश, जो बांग्लादेश से कपड़ा आयात करते थे, वह अब विकल्प तलाश रहे है।

पड़ोसी देश में ऐसे माहौल के बीच भारत के सामने कई समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां बांग्लादेश की ऐसी स्थिति के कारण भारत को फायदा भी हो सकता है।

बांग्लादेश ने चीन के बाद रेडीमेड वस्त्रों एवं वस्त्र उत्पादों के निर्यात में तेज वृद्धि की है, जिससे यह चीन के बाद दुनिया में ऐसे उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। वर्ष 2022 में बांग्लादेश का कपड़ा निर्यात 45 बिलियन डालर था, जो भारत से दोगुने से भी अधिक था।

भारत के पास अवसर है कि वह बांग्लादेश की अराजगी स्थिति के दौरान रेडीमेड उद्योगों के बंद होने का फायदा उठा सकता है और अपना कपड़ा निर्यात भी बढ़ा सकता है। बांग्लादेश से रेडीमेड वस्त्रों का आयात कर रहे देश अब इसकी कमी को संतुलित करने के लिए भारत की ओर रुख कर सकते हैं। इससे भारत सरकार के उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसमें वर्ष 2030 तक कपड़ा निर्यात में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल करना है।

विजित कुमार, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

यदि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक ढंग से रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सके तो विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास को और अधिक गति मिलेगी।

द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत

कुछ व्यक्ति राष्ट्रीय हितों पर सीमित आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं, यह सवाल करते हुए कि क्या राजकोषीय लाभ परिहार्य आयात को उचित ठहराते हैं। कोई भी राजकोषीय लाभ, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार की सुरक्षा के महत्व को कम नहीं कर सकता।

जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, भारत

बुलेट ट्रेन परियोजना एक बहुत ही जटिल और तकनीकी–गहन परियोजना है। सुरक्षा के उच्चतम स्तर को ध्यान में रखते हुए इसे जापान के सहयोग से डिजाइन किया गया है। हम बुलेट ट्रेनों को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित करने और 'आत्मनिर्भर' बनने पर काम कर रहे हैं।

अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री, भारत

स्वदेशी जागरण मंच, बजट प्रस्तावों की सराहना करता है क्योंकि ये रोजगार–केंद्रित, कृषि–समर्थक, व्यवसाय–समर्थक, विशेषकर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) समर्थक हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

विश्व विकास रिपोर्ट–2024 को निरस्त करे भारत

विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसमें भारत समेत इंडोनेशिया, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की गई है। हमारे देश के संदर्भ में विश्व विकास रिपोर्ट का कहना है कि भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के एक–चौथाई तक पहुंचने में 75 साल लग जाएंगे। यानी एक तरह से भारत के वर्ष 2047 तक विनिर्माण विकास पर सवार होकर विकसित अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प का मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है। विश्व बैंक ने हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट में जारी करते हुए यह दावा किया है कि यह 108 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित है, जिनमें दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी रहती है और जो सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारत और इंडोनेशिया की औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि बहुत अधिक विकास के आधार पर तेजी से अमीर बनने के बजाय उन्हें लंबी अवधि के लिए धीमी, लेकिन निरंतर वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मध्यम आय वाले देशों को घरेलू प्रौद्योगिकी विकास का मोह छोड़ देना चाहिए और अन्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों और उनकी कंपनियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रयास संसाधनों की बर्बादी होगी। इस मामले में, इस रिपोर्ट ने सरकारी सहायता देकर विदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण कोरिया की प्रशंसा करते हुए, ब्राजील की यह कहकर आलोचना की है कि उसने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पर कर लगाकर विदेशी प्रौद्योगिकी को हतोत्साहित किया, जिसके दुष्परिणाम उसे भुगतने पड़े। इस रिपोर्ट में भारत को आगाह किया गया है कि वह अपनी स्वयं की तकनीक विकसित करने की कोशिश न करे, जैसा कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने करने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह है कि भारत की सेमीकंडक्टर नीति और रक्षा आत्मनिर्भरता नीति की भी आलोचना की गई है। 'द इकोनमिस्ट' लिखता है कि भारत द्वारा 509 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों की सूची से बाहर हो गया है। रिपोर्ट में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुंपीटर के नाम का इस्तेमाल करते हुए लेखकों ने यह कहने की कोशिश की है कि भारत में सरकारी संरक्षण और नई (विदेशी) फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंधों के कारण कुशल फर्म भी कुशल नहीं रह पाएंगी। रिपोर्ट कहती है कि जहां एक औसत अमेरिकी फर्म 40 साल में आकार में सात गुना बढ़ जाती है, वहीं भारत में यह केवल दोगुनी होती है।

ऐसा लगता है कि विश्व बैंक इस बात से नाराज है कि भारत सरकार ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी के प्रस्ताव और शर्तों को खारिज कर दिया है और आयात शुल्क में पूरी छूट देने से इन्कार कर दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के लेखकों को शायद यह नहीं पता कि भारत के आटोमोबाइल उद्योग का दुनिया में अपना एक अलग स्थान है, जिस कारण देश में आटोमोबाइल कंपनियों ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत आनलाइन लेन–देन (यूपीआइ) में तेजी से विकास कर रहा है, जिसे स्वयं विश्व विकास रिपोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि इसने किस तरह से व्यवसायों, खासकर छोटे व्यवसायों में क्रांति ला दी है। आज भारत का यूपीआइ आनलाइन लेन–देन में दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और कई देश इसे अपनाने के लिए उत्सुक हैं। चूंकि भारत ने यह तकनीक विकसित कर ली है, इसलिए वह स्विफ्ट जैसी अपनी स्वयं की भुगतान प्रणाली बना सकता है। भारत ने मित्र देशों से रुपये में तेल खरीदने जैसे लेन–देन करना शुरू कर दिया है, जो जाहिर तौर पर अमेरिका और यूरोप के देशों को पसंद नहीं है। भारत में इस तकनीक के विकसित होने के बाद वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां बाजार से लगभग बाहर हो गई हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र एक और उदाहरण है जहां भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित कर पीएसएलवी और चंद्रयान जैसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लांच किया। आज स्थिति यह है कि चंद्रयान बनाकर भारत चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। जिस लक्ष्य के लिए अमेरिका को 166 अरब डालर खर्च करने पड़े, भारतीय विज्ञानियों ने उसे केवल 615 करोड़ रुपये में हासिल कर लिया। जबकि विश्व बैंक को समझना होगा कि पिछले पांच वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है और वह रक्षा उत्पादों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर विश्व बैंक का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके साथ ही विकसित औद्योगिक देशों के रक्षा बाजार अब सिकुड़ रहे हैं और दुनिया रक्षा वस्तुओं के लिए भारत की ओर रुख कर रही है।

विश्व बैंक यह क्यों भूल जाता है कि इन सभी तथाकथित 'गलतियों' के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि विकसित देश भयंकर मुद्रास्फीति और संकुचन या ठहराव की स्थिति से गुजर रहे हैं। अधिकांश यूरोपीय देश सबसे खराब मुद्रास्फीति, आर्थिक गिरावट और कर्ज के बोझ से गुजर रहे हैं और भारत भुगतान संतुलन में घाटे से बाहर आ रहा है। रुपये में पहले से बेहतर स्थिरता है, बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, बौद्धिक संपदा में प्रगति हो रही है और पहले की तुलना में कई गुना अधिक पेटेंट दिए जा रहे हैं। वर्ष 2024–25 के केंद्रीय बजट में देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है। बहुआयामी गरीबी में अभूतपूर्व कमी आई है और सभी बेघरों को घर दिए जा रहे हैं। गरीबों को सरकारी सहायता, बिजली, पानी, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही है। इन सबके लिए संयुक्त राष्ट्र के यूएनडीपी जैसी संस्थाओं द्वारा भारत की प्रशंसा की जा रही है। विश्व बैंक को यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 10 हजार डालर से ऊपर पहुंच रही है, जो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का 10 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए अगले 23 वर्षों में उच्च आय वाला देश बनने के भारत के संकल्प का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। विश्व बैंक जिस रिपोर्ट को 108 देशों के आंकड़ों पर आधारित शोध बता रहा है, वह वास्तव में एक मनगढ़ंत लेख है, जिसमें तर्क और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। भारत के नीति निर्माताओं से विशेष अनुरोध है कि ऐसी रिपोर्टों को खारिज करते हुए भारत सरकार को इस पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए।

सरकार की प्राथमिकताओं पर केंद्रित बजट

23 जुलाई, 2024 को पेश किए गए बजट की खासियत यह है कि यह मोदी सरकार की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। निर्मला सीतारमण ने बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की नौ प्राथमिकताएं बताई हैं, जैसे कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन, विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार।

प्रधानमंत्री मोदी से पूर्व, हम अभी तक केंद्र सरकार के जो बजट देखते थे, वो लोकलुभावनवाद से प्रेरित थे, क्योंकि वे अगले चुनाव में वोटों पर नज़र गड़ाए हुए थे। लेकिन मोदी सरकार पहले भी लोकलुभावनवादी के रूप में देखे जाने से बचती रही है और इसके बजाय विकास और समावेशी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती रही है। इस तरह, यह बजट भी उसी राह पर है।

रोजगार पर ध्यान

हम समझते हैं कि रोजगार दो स्रोतों से आता है, पहला, नौकरी और दूसरा स्वरोजगार। स्वरोजगार का लाभ यह है कि स्वरोजगार करने वाले लोग नौकरी के सृजनकर्ता भी होते हैं। इस संदर्भ में बजट में दो बड़ी घोषणाएं हैं। एक, बिना गारंटी वाले मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने से संबंधित है। स्टार्ट–अप को भी एंजल टैक्स के माध्यम से कुछ राहत दी गई है।

कुल मिलाकर, यह एक संतुलित बजट है, जिसमें मध्य वर्ग, गरीब, किसान, युवा और महिला, सभी को साधा गया है। माध्यम वर्ग को थोड़ी ही सही लेकिन आय कर में राहत भी दी गयी है। बजट के कुल प्रावधानों को देखें तो लगता है कि एक सधा हुआ, सही दिशा में उठाया गया कदम है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

दूसरी योजना, रोजगार के संबंध में है और वह भी संगठित क्षेत्र में; इसके लिए तीन योजनाएं शुरू की गई हैं। एक प्रमुख योजना अप्रेंटिसशिप योजना है, जिसके तहत एक अप्रेंटिस को 5000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के वित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेट सीएसआर फंड का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक तरफ़ बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा तो दूसरी तरफ़ व्यवसायों के लिए कुशल

कर्मचारियों की कमी भी दूर होगी। यदि यह योजना सफल होती है, तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। छोटे उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है. फिलहाल सरकार ने केवल बड़े उद्योगों को ही इस योजना में शामिल किया है और इसका कारण यह है कि सीएसआर के माध्यम से जो पैसा आता है, वह इसमें इस्तेमाल हो पायेगा।

इसके अलावा कंपनियों को रोज़गार उपलब्ध कराने की दृष्टि से पहली नौकरी का पहला वेतन सरकार द्वारा देने का वादा भी इस बजट में किया गया है, इसके साथ ही नियोक्ता को ईपीएफ़ओ में प्रोविडेंट फण्ड जमा करने हेतु सहयोग भी दिया जाएगा।

संतुलित व सधा हुआ बजट है

बजट के बारे में सामान्य तौर पर माना जाता है कि यह सरकार की नीतियों का आईना होता है। बीते 10 वर्षों में सरकार जिन नीतियों पर चली है, उस कारण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। चाहे वह संवृद्धि की बात हो या, महंगाई पर रोक लगाने की, सरकार सफल रही है, क्योंकि पिछली सरकार के 10 वर्षों की औसत महंगाई की दर 8.6 थी, जो इस सरकार के समय लगभग छह प्रतिशत है। इन बातों से उत्साहित होकर सरकार ने इस बार के बजट में कई ऐसे प्रावधान किये हैं जो विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं। क्योंकि बार–बार कहा गया है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है। विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे केवल चार ही जातियां दिखाई देती हैं., युवा, महिला, गरीब और किसान।

किसानों की बात करें, तो किसान क्रेडिट कार्ड, सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए एफपीओ का गठन और डेयरी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन समेत

बजट के बारे में सामान्य तौर पर माना जाता है कि यह सरकार की नीतियों का आईना होता है। बीते 10 वर्षों में सरकार जिन नीतियों पर चली है, उस कारण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। चाहे वह संवृद्धि की बात हो या, महंगाई पर रोक लगाने की, सरकार सफल रही है।

तमाम उपाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट में दिखाई देते हैं। जहां तक गरीबों की बात है तो आवास उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में वह तीन करोड़ और शहरी क्षेत्र में एक करोड़ आवास मुहैया करायेगी, यह अच्छा कदम है। आप कल्पना कीजिए की जो कच्चे घर में रह रहा है, यदि उसे पक्का घर मिल जाए, तो निश्चित तौर उसके जीवन स्तर में बदलाव आयेगा। जीवन स्तर में बदलाव से उस व्यक्ति के कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। संभवतः इन्हीं सब कारणों से बीते वर्षों में भारत की बहुआयामी गरीबी में काफी कमी आयी है। यूएनडीपी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया, विशेषकर गरीब देशों की तुलना में बहुआयामी गरीबी को कम करने में हमने अच्छी सफलता प्राप्त की है।

राज्यों की बात करें, तो आंध्र प्रदेश और बिहार की मदद को लेकर कदम उठाने की बात भी बजट में कही गयी है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की बात की गयी है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लागू करने की बात हुई थी। आंध्र के लिए अलग राजधानी बनाने की बात भी तब हुई थी, जिसके लिए केंद्र सरकार की सहायता चाहिए। उसके लिए भी अतिरिक्त राशि देने की बात कही गयी है। बिहार के लिए बजट में 26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में बिहार के लिए जो खास पेशकश की गयी वह यह कि बोधगया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात की गयी है, ताकि अधिक लोग वहां जा सकें। इस तरह बोधगया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास हुआ है। दूसरी बात, बिहार को जो पैसा देने की बात कही गयी है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार इस समय बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। यह राज्य प्रति व्यक्ति आय में न केवल नीचे है, बल्कि विकास में भी पिछड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, यह लंबे समय से बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है। जब से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से लगातार नेपाल सरकार पानी छोड़ देती है, जिससे नेपाल से लगते बिहार के क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ में डूब जाते हैं, जिससे लोगों को बेघर होना पड़ता है, जिसका असर उनकी रोजी–रोटी पर पड़ता है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी इंट्रा स्टेट लिंक समेत अन्य परियोजनाओं को लेकर बजट में विशेष प्रावधान करना अभिनंदनीय कदम माना जाना चाहिए, इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको बिहार की इस त्रासदी को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। महिलाओं के रोजगार वृद्धि को लेकर भी प्रावधान किये गये हैं। कुल मिलाकर, यह एक संतुलित बजट है, जिसमें मध्य वर्ग, गरीब, किसान, युवा और महिला, सभी को साधा गया है।

माध्यम वर्ग को थोड़ी ही सही लेकिन आय कर में राहत भी दी गयी है। बजट के कुल प्रावधानों को देखें तो लगता है कि एक सधा हुआ, सही दिशा में उठाया गया कदम है। ❑❑

हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की भूमिका लिखते हुए हमारे प्रमुख आर्थिक सलाहकार और विद्वान अर्थशास्त्री डा. वी. अनन्त नागेश्वरन ने बड़े स्पष्ट रूप से और तर्क सहित इस बात पर ज़ोर दिया है कि आने वाले दिनों में सारी दुनिया को कृषि के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और एक बार फिर से यह स्वीकार करना होगा कि कृषि ही हमारे जीवन का तथा हमारी अर्थव्यवस्था का दीर्घ स्थायी समाधान और आधार बन सकता है। हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा और आर्थिक विकास में कृषि को ग्रोथ इंजन स्वीकार करना होगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि बदलते हुए भौगोलिक–राजनैतिक परिदृश्य में विशेषकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, आर्टीफिसियल इंटेलिजेन्स तथा कृषि में उपयोग की जाने वाली कीटनाशक तकनीक के प्रयोग से मिट्टी का विषाक्त होना तथा भोजन प्रणाली में स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव का होना, हमें इस बात के लिये आगाह कर रहा है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र एकमात्र विकास का आधार नहीं रह सकता है। इन दिनों श्रम शक्ति वापस कृषि क्षेत्र की तरफ़ माइग्रेट हो रही है और औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में श्रम नियोजन घट रहा है। कृषि संबंधी उद्योग को बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे शहरी युवकों को भी रोज़गार के ज़्यादा अवसर मिलेगें।

भारत@2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, समग्र आर्थिक विकास की अवधारणा के चिंतन में भी कृषि संबंधी सभी विषयों का विश्लेषण ज़रूरी है। खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ कृषि योग्य भूमि और फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये बजट 2024–25 में भी इस विषय पर प्राकृतिक खेती और अच्छी नस्ल के बीजों को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री ने आईसीएआर द्वारा विकसित 109 उत्तम नस्ल की बीजों का अनावरण अभी 11 अगस्त 2024 को किया है तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ाने पर भी बल दिया है, जो बजट 2024–25 में की गई घोषणा के अनुरूप है।

एक नई सोच की आवश्यकता है ताकि 2047 के विकसित भारत के सपनों को साकार करने में हमारा कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सके, हमारे गाँव और किसान आत्मनिर्भर बन सकें तथा सरकार की सब्सिडी पर निर्भर न रहकर स्वाभिमान और स्वावलंबन का उदाहरण बन सकें।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

कृषि का विषय व्यापक है और हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 42.3 प्रतिशत जीविका का आधार तथा ग्राम्य जीवन इसी पर निर्भर है। 1991 में कृषि हमारी राष्ट्रीय आय

का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा होता था, जो अब घटकर मात्र 18.2 प्रतिशत के आस–पास रह गया है। सेवा क्षेत्र, जहां हमारी राष्ट्रीय आय का 55 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा रखता है, वह सिर्फ़ 25–30 प्रतिशत लोगों को रोज़गार देता है, जिसमें बहुत सारा हिस्सा असंगठित क्षेत्र का होता है। शेष लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा उद्योग क्षेत्र से आता है, जिसमें शिल्प 17 प्रतिशत, कंस्ट्रक्शन 9 प्रतिशत और बाक़ी 4 प्रतिशत खनिज और बिजली उत्पादन है। इस रोज़गार वैषम्य को समझने की आवश्यकता है। देश में जो बेरोज़गारी और ग़रीबी की समस्या है, उसका दीर्घगामी समाधान गांवों का विकास और कृषि क्षेत्र का सम्यक् विकास से ही संभव है। नवाचार, तकनीकी अनुसंधान में कृषि शोध विषयों को प्राथमिकता देनी होगी। हाल के वर्षों में सरकार की सकारात्मक सोच तथा इस दिशा में सही कदम उठाने से पिछले 5 वर्षों में औसतन 4.18 प्रतिशत की प्रतिवर्ष की वृद्धि, कृषि क्षेत्र में हुई उन्नति का द्योतक है। फिर भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि कृषि जलवायु पर निर्भर है और पिछले साल 2023–24 में उत्पादन की वृद्धि घटकर सिर्फ़ 1.4 प्रतिशत ही रह गई थी, जो 2022–23 की तुलना में 4.7 प्रतिशत आंकी गई है। चूँकि हमारे कृषि गोदामों में संतोषजनक अनाज के भंडार हैं, जिनका लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सरकार देश के ग़रीबों को मुफ़्त वितरण करती है, जिसकी संख्या 80 करोड़ से भी ज़्यादा है और यह कार्य पिछले 5 वर्षों से निरंतर चल रहा है, इस गिरावट का बाज़ार मूल्यों पर कोई नकारात्मक असर नहीं आने दिया गया। खाद्य सुरक्षा का यह एक अतुलनीय उदाहरण है। भारत खाद्य पदार्थों संबंधित फसलों का निर्यात भी कुल उत्पादन का 7 प्रतिशत कर रहा है और इस दिशा में पूर्णरूप से आत्मनिर्भर है, सिवाय कुछ दलहन के आयात के, जिसके लिये

Chart IX.4: GCF of agriculture & allied sector and GCF as a per cent of Agri GVA

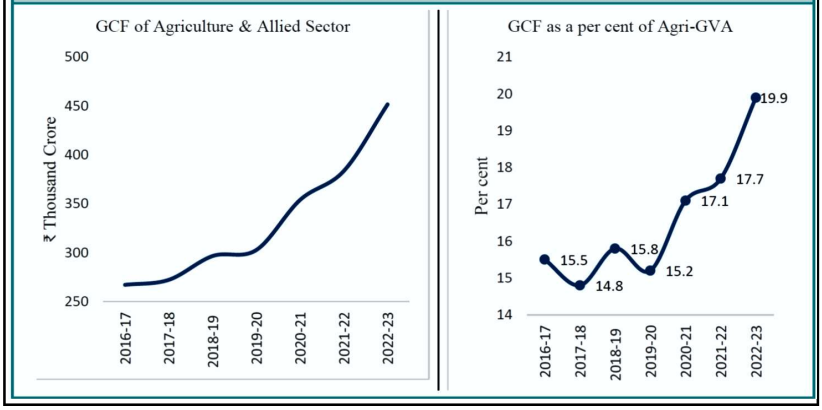

भी सरकार देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये सचेष्ट है। सरकार का कृषि क्षेत्र में एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत पशु पालन, मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन तथा इन सबकी उत्पादकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विश्व स्तर पर ज़्यादातर खाद्य उत्पादों की उत्पादकता दर हमारे देश में तुलनात्मक ढंग से कम है, इसे जैविक खाद तथा प्राकृतिक तरीक़े से खेती के अन्य लाभ की दृष्टि से समग्र भाव से देखने की आवश्यकता है। हमें जीएम फूड से बचने की आवश्यकता है। मात्रात्मक और गुणात्मक कृषि पर ध्यान रखना ज़रूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ आँकड़े दिये गये हैं।

कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश बढ़ाने की तरफ़ सरकार की नज़र है। औसतन वृद्धि 2016–17 से 2022–23 में 9.7 प्रतिशत की दर से हुई है और पिछले दो वर्षों में और भी ज़्यादा रफ़्तार से बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार देश की कुल राष्ट्रीय आय के अनुपात में 2021–22 के 17.7 प्रतिशत से बढ़कर 19.9 प्रतिशत हुई है। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र का विनियोजन बढ़ने की आवश्यकता है।

कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों में कपड़ा, जूट, चाय, फूड प्रॉसेसिंग, चीनी मिल, खाद्य तेल, काफ़ी, रबड़, चमड़ा, डायरी अथवा दुग्ध आदि हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ सहायक उद्योग हैं। इन सभी कृषि संबंधी उद्योगों में रिसर्च तथा नवाचार के आधार पर रोज़गार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।

कृषि उत्पादों के भण्डारण तथा

Chart IX.2: International productivity comparison for major kharif crops (2022)

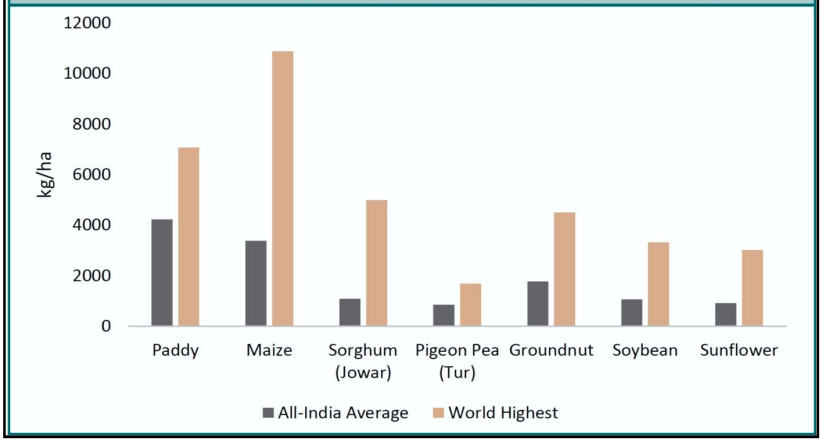

सड़क यातायात को सुविधाजनक बनाने तथा सिंचाई की व्यवस्था अनुकूल बनाने से उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है तथा फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। एथनॉल और मेथनॉल दोनों ही कृषि आधारित ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना ज़रूरी है और इससे एकतरफ़ किसानों की आय बढ़ेगी और दूसरा हमारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और साथ ही पर्यावरण के लिये भी हितकारी सिद्ध होगा।

पिछले कुछ सालों में सरकार ने कृषि क्षेत्र के निर्यात में अच्छी वृद्धि की है। भारत अब दुनिया के सर्वोच्च निर्यात करने वाले 10 देशों में 8वें स्थान पर है। साल 2023 में भारत का कृषि निर्यात 51 बिलियन अमरीकी डालर था, जो साल 2022 के 55 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में थोड़ा कम ज़रूर था, किंतु कुछ भौगोलिक–राजनीतिक कारणों से और कुछ राष्ट्रीय महंगाई को नियंत्रण में रखने की वजह से था, किंतु यह गिरावट प्रायः सभी देशों के लिये सामान्य थी। दुनिया में सबसे बड़े कृषि का निर्यात यूरोप 836 बिलियन अमरीकी डालर और दूसरे स्थान पर अमेरिका है जो 198 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात साल 2023 में किये हैं। कृषि क्षेत्र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा संचालित होता है, जिसके प्रति सदैव जागरूक रहने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र के सामग्र विकास यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृषकों की आय कैसे बढ़े? सरकार ने 2016 में किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया था, किंतु हमारा अन्नदाता अभी भी उत्पादों का सही मूल्य नहीं प्राप्त कर पाता है। सरकार ने न्यूनतम कृषि उपज मूल्य निर्धारण की नीति में कई बार संशोधन किये हैं किंतु किसानों के लागत मूल्य और बाज़ार मूल्य में कहीं न कहीं कुछ फ़र्क़ रह जाता है जो किसानों की समस्याओं को पूरा करने में असमर्थ रह जाते हैं। किसानों की समस्या का जो मूल कारण है वह बहुत ही थोड़ी ज़मीन वाले किसानों से है। हमारे देश में 89.4 प्रतिशत किसानों के सिर्फ़ 2 हेक्टेयर या उससे भी कम ज़मीन है, जिससे उनकी पैदावार लागत ज़्यादा होती है और बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी आर्थिक समस्याएँ बनी रह जाती है। सरकार फसल योजना, तथा किसान क्रेडिट कार्ड तथा मंडियों में ख़रीद आदि से उनकी मौलिक समस्याओं को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। अन्य बहुत सी गांव तथा सरकारी योजनाओं के द्वारा सहकारी (एफपीओ) के द्वारा पूरी तरह से प्रयासरत है किंतु एक नई सोच की आवश्यकता है ताकि 2047 के विकसित भारत के सपनों को साकार करने में हमारा कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सके, हमारे गाँव और किसान आत्मनिर्भर बन सकें तथा सरकार की सब्सिडी पर निर्भर न रहकर स्वाभिमान और स्वावलंबन का उदाहरण बन सकें। ❑❑

लेखक, अखिल भारतीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

कदम-दर-कदम

देश विकास के पथ पर अग्रसर

विकसित देश उसे कहते हैं, जहां तकनीक की मदद से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता हो, बड़े स्तर पर औद्योगीकरण हो, कृषि का यंत्रीकरण किया गया हो, पशुपालन तथा दूध व्यवसाय की स्थिति उन्नत हो रही हो, विकसित यातायात व संचार व्यवस्था हो, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय हो, मनोरंजन की सुविधा हो, सभी आत्मनिर्भर हो, देश में गरीबी न हो, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, परामर्श सेवाएं, शिक्षा आदि की सुविधा सबके लिए उपलब्ध हो, जीवन प्रत्याशा अधिक हो। भारत यह सब हासिल करने की दिशा में तेज गति से बढ़ रहा है। उम्मीद ही नहीं भरोसा किया जा रहा है कि जब भारत 2047 में अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा, तब विकसित देश का लक्ष्य पूरा कर लेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट इसी विकसित भारत का संकेत दे रहा है।

सरकार के पूर्ण बजट में कृषि क्षेत्र को उत्पादनोमुख बनाने, रोजगार सृजन में तेजी लाने, निर्माण व विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने, सेवा क्षेत्र को सबल करने, ग्रामीण व शहरी विकास को सुनिश्चित करने, ऊर्जा की क्षमता में इजाफा करने, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने, नवाचार एवं शोध आदि पर अत्यधिक जोर देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। देश दुनिया की तमाम आर्थिक एजेंसियों की राय में भारत सबसे अधिक तेजी के साथ विकास करने वाला देश है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2024–25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के 6.5 से 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की विकास दर की रफ्तार न सिर्फ संतोषजनक है बल्कि विकसित अर्थव्यवस्था बनने का संकेत है।

भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल होने के लिए सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पीडीपी और एसबीआई के पैमाने पर अनुमान के अनुरूप आगे भी खरा उतरना होगा।

–अनिल तिवारी

भारत की मौजूदा और अनुमानित विकास दर के आधार पर भारतीय और वैश्विक एजेंसियों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था आसानी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी ही बन सकती है। वैश्विक एजेंसी एस.पी. ग्लोबल के अनुसार भारत 2030 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि क्रिस्टल का कहना है कि भारत 2031 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचकर दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी जबकि 2030 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।

यह सारे अनुमान गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय और वैश्विक एजेंसियों के अनुसार भारत की विकास दर 2030 तक 6 से 7 प्रतिशत के बीच रह सकती है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था आसानी से 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है और 2030 तक इसका आकार 7 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है। 'द इंडियन इकोनामीः ए रिव्यू रिपोर्ट' में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक भारत के विकसित देश बनने की बात कही गई थी।

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ–साथ सरकार चाहती है कि आजादी के सौ वर्ष यानी 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। इस सपने को

साकार करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए पूंजीगत खर्च में तेजी लाना जरूरी है। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है, इसीलिए सरकार ने इसके लिए बजट में 2.66 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया है। अन्नदाता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 6 करोड़ किसानों का विवरण लैंड रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की बात बजट में की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड में लाखों किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से अन्नदाता किसान को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

बजट प्रावधानों के अनुसार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कम लागत में किया जा सके। बजट प्रावधानों के मुताबिक सब्जियों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए उसके कलस्टर में वृद्धि की जाएगी। इन प्रावधानों से निश्चित ही कृषि का क्षेत्र और अधिक सशक्त होकर उभरेगा।

बजट में शिक्षा रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड रुपए का आवंटन किया गया है। 5 सालों में 4.01 करोड़ युवाओं को 2 लाख करोड रुपए की लागत से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 10 लख रुपए से 20 लख रुपए तक कर दिया गया है, इससे उन्हें कुछ बड़े स्तर पर कारोबार करने में भी मदद मिलेगी। बजट के अनुसार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी और उन्हें 5000 रूपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस प्रावधान से युवा कौशल युक्त बन सकेंगे और उन्हें रोजगार मिलने में आसानी होगी। बजट में 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं और इस क्रम में आदर्श कौशल ऋण योजना के तहत युवाओं को 7.5 लख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे साल के पहले पूर्ण बजट में यह कहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, छोटे, मझौले उद्योगों के लिए तीन ऋण गारंटी योजना लाएगी ताकि अधिक से अधिक संख्या में उद्यमियों को भी रोजगार मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए 10 लाख करोड रुपए निवेश करने का प्रावधान बजट में किया गया है। शहर में अधिक से अधिक लोगों का खुद का घर हो के लिए आमजन को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने और उन्हें अत्यधिक सब्सिडी की सुविधा दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। बजट में पहली बार 100 शहरों में औद्योगिक पार्क बनाने के लिए भी पहल की गई है ताकि उद्योग और कारोबार को और अधिक बल मिल सके। इन सभी प्रावधानों से यह संकेत मिलता है कि विकास दर में तेजी लाने के साथ–साथ विकास के प्रमुख मानकों को मजबूत करने के लिए बजट में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

जहां तक भारत के 2047 तक विकसित देश बनने का सवाल है तो यह सपना अब धीरे–धीरे हकीकत बनने का इशारा कर रहा है। एक विकसित देश कहलाने के लिए दुनिया के स्तर पर जिन मानकों की जरूरत होती है भारत अपने लगातार प्रयास से धीरे–धीरे उस पर खरा उतरता जा रहा है। यह ठीक है कि एक अति विकसित देश कहलाने के लिए दुनिया के विकसित देशों ने अपने हिसाब से कुछ पैमाने तय कर रखे हैं , संभव है उनके बनाए कुछ पैमानों पर भारत शत प्रतिशत खरा न उतरे लेकिन एक विकसित राष्ट्र कहलाने के लिए जो बुनियादी शर्ते हैं भारत उसे जरुर हासिल कर सकेगा। बजट में इस बात के साफ संकेत हैं। भारत में हाल के वर्षों में तकनीक की मदद से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता बढ़ी है। वृहद स्तर पर औद्योगीकरण हुआ है।

कृषि का यंत्रीकरण लगातार हो रहा है। पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय की स्थिति मजबूत हुई है। विकसित यातायात व संचार व्यवस्था कई गुना अधिक और बेहतर हुई है। देश में सड़कों का जाल बिछा है। शिक्षा की सुविधा हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए समावेशी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जरिए सभी को कौशल युक्त करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा तो बढ़ी ही है मानव विकास सूचकांक में भी भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

कुल मिलाकर भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल होने के लिए सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पीडीपी और एसबीआई के पैमाने पर अनुमान के अनुरूप आगे भी खरा उतरना होगा। एक वृहद दृष्टिकोण के साथ देखा जाए तो 2047 तक भारत की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। लेकिन हमें बहुत अधिक खुश्फहमी पालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया के देशों द्वारा अति विकसित देश के लिए बनाए गए पैमानों पर खुद को मुकम्मल साबित करने के लिए हमें आर्थिक विकास के कुछ और अधिक प्रयास करने ही होंगे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमें नीतियां बनाकर काम करना होगा। आय की असमानता को दूर करने के लिए भी व्यापक और कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। ❑❑

बजट की सकारात्मक दिशा

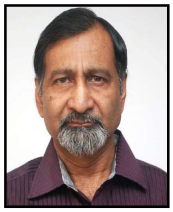

निश्चित ही सरकार योजनाओं पर खर्च करते समय यह कोशिश करती है कि जन–सामान्यों की समस्या का हल निकले और यही कोशिश इस साल के बजट में भी दिखती है।

–अनिल जवलेकर

भारत एक अजीब देश है। यहाँ सरकार की तरफ मदद से ज्यादा राहत की अपेक्षा रहती है। भारत सरकार भी मदद या तो संकट समय में करती है या फिर बहुत गरीब या बहुत अमीर होने पर। लेकिन भारत सामान्य नागरिकों से भरा देश है और सारा देश चलाने की जिम्मेवारी भी इन्हीं पर रहती है। सरकार के सारे खर्चो का बढ़ता बोझ इन्हीं के कंधों पर होता और शायद इसीलिए यह सामान्य जन सरकार से बोझ में थोड़ी राहत की उम्मीद लगाए रहते है। राहत का समय भी साल में एक बार आता है जब सरकार अपने खर्चो का लेखा–जोखा पेश करती है और नए बजट के साथ नए खर्चे और नए कर वसूलने के तौर तरीकों की बात करती है। इस साल के बजट से भी सामान्य जन यही राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला। सरकार का कहना है कि बढ़ते सरकारी खर्चो का ताल–मेल बिठाना मुश्किल होता जा रहा है। यह भी सही है कि बजट में सरकार कुछ लाभकारी योजनाएँ जाहिर करती है जो कुछ हद तक सामान्यों को उपयोगी होती है और राहत का काम करती है। इस साल का बजट भी कुछ ऐसी ही राहत देता दिखता है।

बजट के खर्चे और उसका मिलान

वैसे बजट भारतीय जनता के लिए कोई नयी बात नहीं है। अंग्रेज़ जो बाते छोड़ कर गए है उसमें से बजट भी एक है। बजट की जो खास बात होती है वह यह की बजट पहले खर्चे की बात करता है और बाद में उस खर्चे को पूरा करने के लिए वसूले जाने वाले आय की। इस साल के बजट की बात करें तो खर्चे का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 75 प्रतिशत) सरकारी वेतन, पेंशन, पहले लिए हुए कर्जे के ब्याज और राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से, सबसिडी तथा रक्षा पर खर्च होजाता है। बचे हुए खर्चे में ही विकास योजना वगैरे की बात होती है। आने वाले साल में पूरे 48.21 लाख करोड रुपए खर्च होने है जिसमें से 20.22 लाख करोड से भी कम योजनाओं पर खर्च होने है। बाकी सरकार अपने कामकाज पर खर्च करेगी। इसे वसूलने के लिए जो तरीके है उसमें से एक है करों का जाल (जिससे 25.84 लाख करोड़ रुपये जमा होने है) और दूसरा है कर्जे (16.91 लाख करोड़ रुपये)। करों में

जीएसटी, आय कर, और कार्पोरेशन कर मुख्य है। खास बात यह है कि जीएसटी तो सभी सामान्य जन देते है पर आय कर और कारपोरेट बहुत कम। सरकार को कर्जे देने वाले में भी सामान्य पीछे नहीं है। वे अपनी पूंजी पोस्टल सेविंग्स, प्रव्हिडेंट फंड, वगैरे (4.50 लाख करोड़ रुपये) में रखते है, जो सरकार कर्जे के रूप में उपयोग में लाती है। बाकी बचा कर्जा (11.63 लाख करोड़ रुपये) बाजार से लेने की बात है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि भारत सरकार अपने आप पर याने सरकारी कामकाज पर जो खर्चा करती है वह उसकी आय से ज्यादा है। मतलब कमाई कम और खर्चा ज्यादा वाली बात है। बजट में राजस्व घाटा है और उसे पूरा करने के लिए भी उधार लेना पड़ता है जो कि अच्छी बात नहीं है। यह सही है कि सरकार बचे कर्ज की रकम से विकास करने की कोशिश करती है।

रोजगार समस्या का हल ढूँढने की कोशिश

निश्चित ही सरकार योजनाओं पर खर्च करते समय यह कोशिश करती है कि जन–सामान्यों की समस्या का हल निकले और यही कोशिश इस साल के बजट में भी दिखती है। भारतीय जन सामान्य की मुख्य समस्याओं में से एक है बेरोजगारी। ऐसा नहीं है कि यह भाजपा के शासनकाल में उभरी है। वह हमेशा से रही है और जबसे स्कूल–कॉलेज बढ़े है, पढे–लिखे लोग भी बढ़ रहे है और शिक्षित लोगों की बेरोजगार समस्या गंभीर होती जा रही है। नए तंत्र ज्ञान का उपयोग होने से बड़े उद्योग जरूरी रोजगार उपलब्ध नहीं कर पा रहे है। सर्विस उद्योग जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है उसमें रोजगार अवसर भी कम है। जो भी रोजगार निर्माण हो रहे है वे असंघटित क्षेत्र में हो रहे है। इसलिए सरकार की कोशिश रोजगार अवसर बढ़ाने की है और इस बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ अनुदान देने की बात की गई है। जो उद्योग रोजगार देगा उसको और रोजगार मिलने वाले युवक को अब मदद मिलेगी। पहली बार रोजगार मिलने पर वेतन का कुछ हिस्सा सरकार देगी। उद्योगों को सरकार नए रोजगार देने पर प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा कुछ साल तक देगी यह भी एक अच्छी बात है। दूसरी ओर बेरोजगारों का कौशल बढ़ाने की बात भी बजट करता है जिसमें उद्योग भी शामिल होंगे। यह कितना कारीगर साबित होगा यह देखने वाली बात होगी। कौशल बढ़ाने के लिए कर्ज मुहैया करने की बात भी इस बजट ने की है। मुद्रा लोन को बढ़ाने की भी एक बात है। यह योजनाएँ रोजगार निर्माण करने में सहायक हुई तो निश्चित ही रोजगार समस्या की गंभीरता कम होगी।

कृषि को संवारने की योजना

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और पर्यावरण बदलाव का असर कृषि पर सबसे ज्यादा है। पर्यावरण बदल रहा है इसमें अब शंका लेने का कोई कारण नहीं है। होने वाले बदलाव को रोकने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सरकार ने अपने बजट में इस ओर कदम बढ़ाए है, यह अच्छी बात है। यह सभी जानते है कि कृषि अनुसंधान की दिशा अब भी संकरीत बीजों और जहरीले कीटकनाशक के निर्माण पर टिकी हुई है। बजट में इस बार इस तरह के अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा करने एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि संशोधन पर ध्यान देने की बात की है। कृषि के लिए उपयोगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात भी इस बजट की एक उल्लेखनीय बात है। यह जरूर है कि कृषि अनुसंधान में निजी कंपनियों के सहयोग पर भारतीय किसान संघ ने आपत्ति जताई है। नैसर्गिक कृषि को बढ़ावा देने की बात भी उपयोगी कहलाएगी।

समान्यों को राहत भी देनी होगी

भारत में करों का बहुत बड़ा जाल है और वह जटिल भी है उसे कम करने की बात इस बजट की विशेषता कह सकते है। यही एक सामान्यों को बड़ी राहत है। करों में कटौती से ज्यादा परेशानी करों की जटिल व्यवस्था के कारण होती है। वैसे छूट कम होने से सामान्यजन दुखी है। कीमतें बढ़ रही है और उसका रिश्ता कही न कही करों के स्लैब, दर और छूट की आय से होना चाहिए। लेकिन बजट की भी अपनी मर्यादा है। जब खर्च ही ज्यादा है तो क्या करें।

बजट की दिशा तो सही लेकिन काँटों का ध्यान जरूरी

बजट में घोषित नई योजनाएं जो चल रही है वे सारी योजनाएँ तो अच्छी है, जो भारतीय व्यवस्था को विकसित भारत बनाने में मदद करेंगी। लेकिन यह भी सही है कि इतने से काम नहीं होगा। कौशल प्राप्ति में मदद और पहले रोजगार मिलने पर वेतन वगैरे से रोजगार समस्या हल नहीं होगी। भारतीय उत्पादन और सर्विस क्षेत्रों में बढ़ोतरी और उसमें अधिक रोजगार उपलब्ध करने से ही बात बनेगी। ग्रामीण उद्योगों को भी नए नजरिये से देखना होगा और उसमें ज्यादा पूंजी लगानी होगी तभी कुछ हद तक हल निकलेगा। शैक्षणिक अभ्यास क्रम में कौशल निर्माण विषय लाना होगा और कंपनियों में एप्रेंटिसशिप का उसको मिलाना होगा तभी युवा में पदवी के साथ आत्मविश्वास आयेगा। कृषि में भी अनुसंधान के साथ बहुत सी नीतियाँ बदलनी होगी, चाहे वह आधारभूत कीमती की नीति हो या फिर खाद सब्सिडी की। पर्यावरण का मुक़ाबला कांटों भरा है यह नहीं भूलना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है बजट ने दिशा तो बतलाई है लेकिन उस पर अमल बहुत सी बातें तय करेगा।❑❑

समावेशी विकास पर सरकार का जोर

लोकसभा के चुनाव परिणामों ने सरकार को बेरोजगारी के विषय पर गंभीरता से सोंचने के लिए विवश किया है, जिसकी प्रतिध्वनि मोदी 3.0 सरकार के पहले पूर्ण बजट में भी सुनाई दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट–2024 में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का खाका तैयार किया गया है। युवाओं और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। बजट में 5 साल की अवधि में 2 लाख करोड रुपए के केंद्रीय परिवहन के साथ 4.5 करोड़ युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं शामिल की गई है। वित्तमंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन दिया है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है।

युवाओं में कुशलता बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में सिर्फ 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर की बात प्रमुखता से कही गई है। बजट में सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगले 5 वर्षों के लिए सरकार रोजगार कौशल मध्य और लघु उद्योगों और मध्यम वर्ग की ओर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार की गंभीरता इससे भी स्पष्ट होती है कि रोजगार और कौशल के विभाग का नाम भी बदलकर कौशल रोजगार और आजीविका कर दिया गया है।

दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों की नजर भारत के इसी विशाल उपभोक्ता बाजार पर टिकी हुई है। इस बाजार का लाभ युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें सीधे उद्यम से जोड़कर, प्रशिक्षित युवाओं को उत्पादकता में लगाकर हासिल कर सकते हैं। शायद सरकार की यही मंशा भी है, और सरकार ने अपने पूर्ण बजट में इसका साफ संकेत भी दे दिया है।

–शिवनंदन लाल

कौशल को बढ़ाने के लिए हर साल 25000 छात्रों को शिक्षा ऋण मॉडल का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए कौशल ऋण योजना की राशि को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। कौशल पर ध्यान केंद्रित करने वाली इस योजना से 20 लाख व्यक्तियों को लाभ होगा। युवाओं में कौशल की कुशलता बढ़ाने के लिए 1000 प्रशिक्षण संस्थानों और नए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों की स्थापना भी सुनिश्चित की जाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण प्रदान करने की भी बात कही गई है, जिसके अंतर्गत हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के तीन प्रतिशत ब्याज की छूट भी मिलेगी।

भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, जो सदैव अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती पूर्ण रहा है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव संसाधन विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का हर तीसरा युवा बेरोजगार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर मई 2024 की 7 प्रतिशत के दर से बढ़कर जून महीने में अपने उच्चतम स्तर 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है। भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी 30 प्रतिशत के आसपास बढ़ी है। वर्ष 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2 प्रतिशत थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7 प्रतिशत हो गई। श्रम संगठन की रिपोर्ट को माने तो भारत में कुल बेरोजगारों में 80 प्रतिशत के आसपास युवा है। भारत में कुल श्रम शक्ति का 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है जो विश्व का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाते कार्य बल्कि जरूरत को पूरा करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में वर्ष 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है।

हाल के दिनों में आई तमाम रिपोर्ट से यह बात उभर कर आई है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी की दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगारी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले 60,000 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए लगभग 47

लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इसी तरह रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी श्रेणियों की भर्ती परीक्षा के लिए 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं ने आवेदन पत्र भरा था। देश की सबसे बड़ी नौकरी भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक के लिए सीमित पदों की तुलना में भारी संख्या में प्रतिभागिता की जाती रही है। शिक्षित आबादी का एक बड़ा हिस्सा हर हाल में सरकारी नौकरी पाने के लिए जी–तोड़ मेहनत करता है। इससे एक बात यह भी निकाल कर आती है कि युवा आबादी के पास उचित कौशल ना होने के कारण वह उत्पादक काम की बजाय सरकारी नौकरियों के पीछे भागने में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता रहा है। एक भरोसेमंद रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल कार्य बल के तीन प्रतिशत लोग ही औपचारिक रूप से कुशल श्रमिक हैं जबकि चीन में यह आंकड़ा 24 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत, यूके में 68 प्रतिशत और जापान में 80 प्रतिशत से अधिक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थानों आईआईटी, आईआईएम की बात छोड़ दें तो देश के अधिकांश विश्वविद्यालय कॉलेज और निजी शैक्षणिक संस्थान केवल डिग्रियां बांटने के संस्थान के रूप में चर्चित है। ऐसे संस्थान डिग्रियां बांटकर प्रतिवर्ष देश में शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी एक बड़ी समस्या है। तमाम संस्थान विद्यार्थियों का प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें जिस तरह की उत्पादक शिक्षा देनी चाहिए इसका घोर अभाव है। अधिकांश विश्वविद्यालय और कॉलेज की शिक्षा उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

बजट प्रावधानों के अनुसार ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15 हजार रुपए तक दिया जाएगा जिसकी पात्रता सीमा एक लाख रुपए प्रति माह तक होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है। बजट में नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करते हुए यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफओ योगदान के लिए नियोक्ताओं को 2 साल के लिए प्रतिमाह 3 हजार रुपए तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। योजना का उद्देश्य 50 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। वित्तमंत्री द्वारा बजट में किया गया यह प्रावधान निश्चित रूप से सराहनीय है क्योंकि इससे सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिकता के बीच की खाई को कम करने में मदद मिलेगी एवं अधिकाधिक स्नातकों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में सरकार ने रोजगार देने की दिशा में बड़े फैसले लिए हैं लेकिन इस दिशा में और अधिक गंभीर उपाय किए जाने की जरूरत है जिससे युवाओं को नौकरी करने की मानसिकता से बाहर निकाल कर व्यवसाय करने की दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके।

स्वदेशी जागरण मंच की देखरेख में बहुत पहले से ही इस समस्या को भांपते हुए स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में भारत भर से लोग जुड़ रहे हैं तथा अपने स्वयं का कारोबार विकसित कर रहे हैं। स्वावलंबी भारत अभियान का नारा है कि युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है। लाखों शिक्षित नौजवान अभियान से जुड़ अपना छोटा–मोटा उद्यम शुरू कर नित नई सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के स्तर पर जरूरी है कि एमएसएमई की तरफ युवाओं के रुझान को बढ़ाने के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए जिसके लिए बैंकिंग उद्योग, सरकार आदि पक्षों को एक मंच पर लाकर युवाओं को प्रतिस्पर्धी बनाने, डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के द्वारा स्वरोजगार की दिशा में ढाला जा सके। अनौपचारिक क्षेत्र की श्रम शक्ति को कौशल से लैस करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाले कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रतिष्ठित उद्योगों के साथ सीधे जोड़ा जाना चाहिए। मोटे तौर पर रोजगार सृजित करने के लिए प्रत्येक उद्योग के लिए व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए गए विशेष पेंशन को लागू किए जाने की भी अब जरूरत है।

भारत विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है। 29 वर्ष की औसत आयु के साथ यहां की युवा आबादी में देश को आगे बढ़ाने की पर्याप्त सामर्थ्य है। राष्ट्रीय रोजगार नीति में व्यापक फेर बदलकर हर हाथ को काम दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि देश में जब सभी के पास काम होंगे तो उपभोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे निवेश और बचत में भी वृद्धि होगी। फलस्वरुप अर्थव्यवस्था की गति भी उसी रफ्तार से तेजी पकड़ेगी। भारत के उपभोक्ता बाजार का आकार लगातार बड़ा होते हुए 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का हो गया है। भारत आज दुनिया के नक्शे पर चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन चुका है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों की नजर भारत के इसी विशाल उपभोक्ता बाजार पर टिकी हुई है। इस बाजार का लाभ युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें सीधे उद्यम से जोड़कर, प्रशिक्षित युवाओं को उत्पादकता में लगाकर हासिल कर सकते हैं। शायद सरकार की यही मंशा भी है, और सरकार ने अपने पूर्ण बजट में इसका साफ संकेत भी दे दिया है। ❑❑

आर्थिक विकास को गति देने वाला बजट

हाल ही में लोकसभा के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुनः सौंपी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भारतीय संसद में पेश किया है। इस बजट के माध्यम से भारत की आर्थिक विकास दर को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करना एवं उनके कौशल को विकसित करना, गरीब नागरिकों को भी विकास में हिस्सेदारी देना एवं उन्हें सामाजिक न्याय देना, विनिर्माण इकाईयों को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्रों को विकसित करना, ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आधारभूत ढांचा विकसित करना, नवाचार, शोध एवं विकास करना तथा नई पीढ़ी के सुधार कार्यक्रमों को लागू करना।

केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत खर्चों में लगातार की जा रही वृद्धि के चलते भारत की आर्थिक विकास दर को पंख लगते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2022–23 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसमें 33 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया था। अब वित्तीय वर्ष 2024–45 के लिए इसे और आगे बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में न केवल स्थिरता दिखाई देने लगी है बल्कि यह लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है। आज पूरे विश्व में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रही है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के समय में भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक पर्यटन को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन से देश में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब वर्ग की आय में बेतहाशा वृद्धि हो रही है।

–प्रहलाद सबनानी

बजट का गहराई से अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि केंद्र सरकार ने अब भारत में रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने की ठान ली है। भारत के युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं कौशल विकसित करने की दृष्टि से 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाओं के एक पैकेज की घोषणा की है। शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की राशि इस बजट में आबंटित भी कर दी गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत ईपीएफओ के प्रथम बार सदस्य बनने पर औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के ईपीएफओ खातों में एक माह का वेतन जमा किया जाएगा। इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत एक माह का वेतन (15000 रुपए की अधिकतम राशि तक) तीन किश्तों में उनके खातों में जमा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक माह में एक लाख रुपए तक का वेतन पाने वाली कर्मचारी ही पात्र होंगे। इससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होने की संभावना बजट में व्यक्त की गई है।

ऐसे भी कई निर्णय लिए जा रहे हैं जिनसे आने वाले समय में धरातल पर युवाओं को लाभ होता दिखाई देगा। एक करोड़ युवाओं को आगामी 5 वर्षों के दौरान इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत काम दिया जाएगा। ताकि ये युवा वर्ग के नागरिक रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम

हो सकें। इन युवाओं को प्रति माह 6,000 रुपए तक का वाजीफा सम्बंधित कम्पनियों द्वारा अदा किया जाएगा। वजीफे की इस राशि को कम्पनियों के लिए लागू निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत किया गया खर्च माना जाएगा। भारत की सबसे बड़ी 500 कम्पनियों को इस योजना के अंतर्गत युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा देनी होगी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा भी इन युवाओं को प्रतिमाह 5000 रुपए अदा किए जाएंगे। यह केंद्र सरकार का एक सूझबूझ भरा निर्णय कहा जा सकता हैं। साथ ही, विनिर्माण के क्षेत्र के रोजगार के नए अवसर निर्मित करने की पहल भी की जा रही है। नए कर्मचारियों के ईपीएफओ खाते में जमा होने वाली राशि को आगामी 4 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इससे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों को ही लाभ होगा। इस योजना का लाभ 30 लाख युवाओं को होने जा रहा है। एक अन्य योजना के अंतर्गत नियोक्ता को अपने नए कर्मचारियों के ईपीएफओ खातों में जमा की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति आगामी 2 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इससे रोजगार के 50 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के समय में भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक पर्यटन को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन से देश में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब वर्ग की आय में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। श्री विष्णुपाद मंदिर कोरिडोर, गया, बिहार एवं श्री महाबोधि मंदिर कोरिडोर बोधगया, बिहार को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार देश में अन्य मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है ताकि देश में इन मंदिरों में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो तथा भारत को वैश्विक पटल पर एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में दिखाया जा सके।

भारत के ग्रामों में निवास कर रहे नागरिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन करते हैं। अतः ग्रामों में ही रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की मद पर 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह सुविधा तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त ऋण के व्यवसाईयों को प्राप्त होगी एवं जिन्होंने पूर्व में लिए गए 10 लाख रुपए के ऋण की राशि को समय पर अदा कर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भी ऋण की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक करोड़ आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन एक करोड़ आवासों पर 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा, इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 2.2 लाख करोड़ रुपए की रहेगी। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 करोड़ आवासों का निर्माण करने की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी है।

देश के आर्थिक चक्र को गति देने के उद्देश्य से नई कर प्रणाली के अंतर्गत वेतनभोगी/पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए सामान्य छूट की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही, आय कर की दरों में कुछ इस प्रकार का संशोधन किया गया है कि 15 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 17,500 रुपए का लाभ होगा। इस निर्णय से मध्यम वर्गीय नागरिकों के हाथों में कुछ अधिक राशि बचेगी और इस राशि इस इनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था के चक्र में मजबूती आएगी।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट में कुल आय का अनुमान रुपए 31.07 लाख करोड़ रुपए का लगाया गया है, इसमें ऋण की राशि शामिल नहीं है परंतु, करों के मद से प्राप्त होने वाली 25.83 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। जबकि, कुल खर्च का अनुमान 48.21 लाख करोड़ रुपए का लगाया गया है। ❑❑

प्रहलाद सबनानी, सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.

बजट में कृषि और ग्रामीण विकास

बजट 2024–25 बुनियादी ढांचे के संवर्द्धन और कृषि आत्मनिर्भरता के विकास दोनों को प्राथमिकता देकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए आधार तैयार करता है।

–डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह व आदित्य प्रताप सिंह

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में दो अलग–अलग क्षेत्रों को समर्थन दिया गया है। ये दोनों क्षेत्र है – ग्रामीण क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)। यह दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे है जो अक्सर विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते रहे हैं। अब भी ये दोनों क्षेत्र कोरोना महामारी के प्रभावों से जूझ रहे हैं। भारत का लक्ष्य वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना है, और यह लक्ष्य इन दोनों क्षेत्रों के व्यापक योगदान पर निर्भर है। इस परिप्रेक्ष्य में, अंतरिम बजट में विभिन्न उपाय शामिल किये गये थे, ताकि इन क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर आवश्यक गति दी जा सके। चुनावी असफलताओं के बाद, इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने और वित्तीय रूप से मजबूत करने की उम्मीदें बढ़ गई थीं। लेकिन मोदी 3.0 सरकार के पहले पूर्ण बजट में बजट भविष्यवाणियों की तुलना में कोई खास वृद्धि नहीं हुई।

हालाँकि कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। सरकार पर इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने का दबाव है। सच है कि देश के जीडीपी के आंकड़े लगातार चमकते हुए दिख रहे है, लेकिन इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी अथवा उदासीनता के कारण हमें बेरोजगारी, आय असमानता, आदि के मोर्चे पर अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार ने कई तरह के समावेशी कार्यक्रमों के जरिये इन दोनों क्षेत्रों को भरपूर सहयोग देने का इंतजाम बजट में किया है, जो कि विकसित भारत के दृष्टिकोण से एक स्वागत योग्य कदम है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वैश्विक बाजारों में जीत हासिल करने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों की उम्मीद कर रहे थे। बजट में कई वित्तीय और नियामक सुधार शामिल थे, जिनमें ऋण गारंटी योजना, नए मूल्यांकन मॉडल, ई–कॉमर्स सुविधा केंद्र और गुणवत्ता परीक्षण केंद्र शामिल थे। ये परिवर्तन एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम का दावा है कि यह उपकरणों में निवेश को वित्तपोषित करने के लिए बिना किसी संपार्श्विक या अन्य पार्टी की गारंटी के टर्म लोन प्राप्त करना संभव बनाता है। इसके अलावा, सीतारमण ने बताया कि इस कार्यक्रम का संचालन इन एमएसएमई से जुड़े क्रेडिट जोखिमों को एकत्रित करके किया जाएगा। एक विशिष्ट स्वयं–वित्त पोषण कार्यक्रम के परिचय के माध्यम से, एमएसएमई अब 100 करोड़ रुपये तक के ऋण गारंटी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े ऋणों के लिए भी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने तनाव के समय में वित्तपोषण में सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया ताकि ये कंपनियाँ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते समय भी वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाए रख सकें। मुद्रालोन कार्यक्रम के तहत अधिकतम ऋण राशि उन लोगों के लिए 20 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है जिनके पास अपने ऋणों को चुकाने का प्रमाणित तरीका है। यह एक बड़ा वित्तीय लाइफलाइन प्रदान करता है, जो इस व्यवसाय के सामने सबसे अधिक दबाव वाली आवश्यकताओं में से एक है।

सार्वजनिक बैंकों ने अब एमएसएमई ऋणों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए एक कंपनी की डिजिटल उपस्थिति के आधार पर मूल्यांकन करने की योजना बनाई है। पहले, सार्वजनिक बैंक एमएसएमई ऋणों की पात्रता का निर्धारण केवल पारंपरिक वित्तीय

दस्तावेजों के आधार पर करते थे। इस कदम से विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह नवाचार छोटे उद्यमों को धन तक पहुंचने के तरीके में मौलिक रूप से बदलाव लाएगा जो औपचारिक लेखांकन प्रणाली नहीं रखते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार की योजना अगले तीन वर्षों में एमएसएमई हब में स्थित एसआईडीबीआई शाखाओं की संख्या बढ़ाने की है। उनकी योजनाओं के अनुसार, अगले तीन वर्षों में भारत के 242 प्रमुख एमएसएमई समूहों में से 168 में एसआईडीबीआई की शाखा स्थापित करने का लक्ष्य है।

ध्यान देने योग्य है कि भारत के 1,300 औद्योगिक समूहों में से एक में से एक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेषज्ञता है। इस कारण से, भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में उद्योग की परीक्षण आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से पचास बहु–खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता आवंटित की गई है।

2019–20 वित्तीय वर्ष से, भारत में ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन में लगातार वृद्धि हो रही है, और इस वर्ष यह पहले ही 2.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी है। जब पहले से उपलब्ध स्तरों की तुलना की जाती है, तो यह लगभग एक लाख करोड़ रुपये की जबरदस्त वृद्धि है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुधार में योगदान देना है। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की प्रस्तुति शामिल थी। इस चरण का उद्देश्य सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों के नेटवर्क का निर्माण करना था। यह नेटवर्क 25,000 ग्रामीण बस्तियों की सेवा करने के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्तपोषण लगभग 37 प्रतिशत घटा दिया गया है, जो पिछले वर्ष के 19,000 करोड़ रुपये से घटकर 12,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो संशोधित अनुमान 17,000 करोड़ रुपये से काफी कम है। यह बावजूद कि लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी है।

कृषि के पुनर्जीवित करने के लिए अनुसंधान और विकास के साथ–साथ आपूर्ति श्रंखलाओं के संवर्द्धन पर विशेष ध्यान देने के साथ, 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस निवेश से दलहन और तिलहन के उत्पादन, भंडारण और विपणन में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे सरसों, मूंगफली और सोयाबीन जैसी आवश्यक फसलों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हालांकि, व्यापक कृषि उत्पादन के बावजूद, कमजोर आपूर्ति नेटवर्क ने खेती समुदाय के विस्तार को सीमित कर दिया है। कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण और विपणन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, बजट में उपभोक्ता केंद्रों के निकट बड़े पैमाने पर उत्पादन समूहों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, बजट में किसान–उत्पादक संगठनों (ईपीओ), सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स की सहायता को बढ़ावा दिया गया है।

एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण का भी प्रस्ताव है, और इसे विकास प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है। अगले तीन वर्षों में, 400 जिलों में खरीफ फसलों का एक डिजिटलीकृत सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण की सहायता से, छह करोड़ किसानों का डेटा राष्ट्रीय रजिस्टर में एकीकृत किया जा सकेगा, जिससे सेवाओं तक तेजी से पहुंच प्राप्त होगी।

वित्तमंत्री ने एक नया राष्ट्रीय सहयोग योजना पेश किया है जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में अमूल की उपलब्धियों को दोहराना है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण नगर–पालिकाओं में आर्थिक विकास और नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। हालाँकि, सभी वादे पूरे नहीं हुए; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) का बजट 86,000 करोड़ रुपये बना रहा, जो अभी भी 2022–23 में आवंटित 90,800 करोड़ रुपये से कम है।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास की मौलिक आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घरों के निर्माण की योजना का उद्देश्य इस मांग को पूरा करने के लिए लाखों लोगों को आवश्यक आवास प्रदान करना है। यह बजट बुनियादी ढांचे के संवर्द्धन और कृषि आत्मनिर्भरता के विकास दोनों को प्राथमिकता देकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए आधार तैयार करता है। ❑❑

बजट और मध्यम वर्ग

नई सरकार के गठन के बाद 23 जुलाई 2024 को संसद में पूर्ण बजट के रूप में बजट 2024–25 पेश किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की राजस्व स्थिति को देखते हुए मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के विभिन्न स्लैब में बदलाव करके यह सुनिश्चित भी किया कि सभी करदाताओं को अधिकतम 17,500 रुपये की राहत मिले। लेकिन 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों, खासकर उच्च–मध्यम वर्ग को मिलने वाले लाभ को भी 17,500 रुपये तक सीमित कर दिया गया। लेकिन, 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों की शिकायत है कि बजट में मध्यम वर्ग को आम तौर पर नजरअंदाज किया गया है।

इस शिकायत के बारे में 'फैक्ट चेक' करने की जरूरत है, ताकि यह समझा जा सके कि क्या वाकई वित्त मंत्री ने बजट 2024–25 में मध्यम वर्ग को नजरअंदाज किया है। यह समझने की जरूरत है कि मध्यम वर्ग असल में है क्या? भारत में अलग–अलग एजेंसियां मिडिल क्लास को अलग–अलग तरीके से परिभाषित करती हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) 2 से 20 लाख रुपये सालाना कमाने वाले परिवारों को मिडिल क्लास में शामिल करता है। एनसीएईआर के मुताबिक मिडिल क्लास की तीन कैटेगरी हैं, एक, निम्न–मध्यम वर्ग, जिसमें 2 से 5 लाख रुपये तक कमाने वाले परिवार शामिल हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग हैं; 5 से 10 लाख रुपये तक कमाने वाले परिवार मध्यम वर्ग कहलाएंगे और 10 से 20 लाख रुपये तक कमाने वाले परिवार उच्च–मध्यम वर्ग कहलाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक 3.5 लाख रुपये से 17.5 लाख रुपये तक कमाने वाले परिवारों को मिडिल क्लास में शामिल करता है। भारत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में उन परिवारों को शामिल करती है, जिनकी आय 8 लाख रुपये से कम है तथा क्रीमी लेयर को उच्च–मध्यम वर्ग को परिभाषित करते हुए उन लोगों को उसमें शामिल करती है, जिनकी आय 12 लाख रुपये से अधिक है।

आयकर विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2022–23 में देश में कुल 7.4 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया, लेकिन उनमें से केवल 2.24 करोड़ लोगों ने ही वास्तव में आयकर का भुगतान किया। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले 7.4 करोड़ में से 5.8 करोड़ लोगों ने 10 लाख रुपये तक की आय घोषित की। यानी यह समझा जा सकता है कि रिटर्न दाखिल करने वाले कुल लोगों में से 78 प्रतिशत ने 10 लाख रुपये या उससे कम घोषित किया। यह समझा जा सकता है कि वित्त मंत्री ने आयकर छूट देते हुए 10 लाख रुपये से कम आय वालों को ही आयकर रियायत दे कर एक बड़ी संख्या में करदाताओं को राहत देने का प्रयास किया है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि संगठित क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को पहला वेतन सरकार देगी। इस प्रावधान से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है।
–स्वदेशी संवाद

यह तो सभी जानते हैं कि बजट का मतलब सिर्फ़ टैक्स या इनकम टैक्स नहीं होता, इसलिए इस बार बजट में मध्यम वर्ग के लिए वित्तमंत्री ने क्या रखा है, इसे विस्तार से समझना होगा। सरकार के बजट से महिलाओं को मिलने वाले फ़ायदों के आधार पर बजट का आकलन करने की परंपरा रही है। इसे जेंडर बजटिंग कहते हैं। इसी तर्ज़ पर हम बजट का आकलन इस आधार पर कर सकते हैं कि बजट से मध्यम वर्ग को कितना फ़ायदा मिलने वाला है।

सबसे पहले आज मध्यम वर्ग को अपनी अगली पीढ़ी के रोजगार की सबसे ज्यादा चिंता है। इस साल के बजट में सरकार ने युवाओं में कौशल विकास और रोजगार सृजन तथा प्रोत्साहन के लिए बड़ी राशि आवंटित की है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि संगठित क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को पहला वेतन सरकार देगी। इस प्रावधान से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा नई भर्ती में नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए किया जाने वाला अंशदान 2 साल तक सरकार द्वारा दिया जाएगा। बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें पांच साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने की योजना भी शामिल है। बजट में युवाओं के लिए लाई गई सबसे बड़ी योजनाओं में से एक 500 बड़ी कंपनियों में 'इंटर्नशिप योजना' है। इस योजना के तहत प्रत्येक युवा को 5000 रुपये प्रति माह की राशि और 6000 रुपये का एकमुश्त लाभ दिया जाएगा। इस योजना से 5 साल में 1 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। यह योजना युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें रोजगार के योग्य बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों में बेरोजगार युवाओं के लिए, इस बजट में इन सभी योजनाओं के तहत बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।

दूसरा, सरकार प्रधानमंत्री सूर्य मुफ़्त बिजली योजना लागू कर रही है, जिसके तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली मिलेगी, जो अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए सोलर पैनल खरीदने के लिए सब्सिडी के साथ–साथ लोन भी दिया जाएगा। इससे लाभार्थी को सोलर पैनल लगवाने की लागत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

तीसरा, सरकार ने इस साल के बजट में 11,11,111 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की घोषणा की है, जिससे देश में सड़क, रेल, जल और हवाई परिवहन सहित बुनियादी ढाँचे के निर्माण में मदद मिलेगी। इससे न केवल मध्यम वर्ग के लिए परिवहन और जीवन आसान होगा, बल्कि इससे रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, जिससे देश में वस्तुएँ और सेवाएँ सस्ती हो सकती हैं।

चौथा, गाँवों में 3 करोड़ घरों के सरकारी सहायता प्राप्त निर्माण के अलावा, शहरों में भी एक करोड़ घर बनाए जाएँगे, जिससे निम्न–मध्यम वर्ग को लाभ होगा और वे किफायती आवास का लाभ उठा पाएँगे।

पांचवां, सरकार ने जिस तरह से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स को खत्म किया है, उससे मध्यम वर्ग के युवाओं को फायदा हो सकता है।

छठा, यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आयात शुल्क कम किए गए हैं, उसका अप्रत्यक्ष लाभ मध्यम वर्ग को भी मिलेगा क्योंकि उन्हें सस्ता सामान मिलेगा।

सातवां, सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया है, जिससे अगले कुछ वर्षों में शोध और नवाचार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे 50 वर्षों की अवधि में वापस किया जा सकता है। इसके अलावा, बजट में किए गए विभिन्न प्रावधानों से मध्यम वर्ग को होने वाले लाभों का आकलन करने की आवश्यकता है। तभी हम सही ढंग से आकलन कर पाएंगे कि बजट प्रावधानों से मध्यम वर्ग को कितना लाभ होगा। यह समझना होगा कि हम केवल कर छूट के आधार पर यह आकलन नहीं कर सकते कि बजट से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है।

हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय के हित में सरकार अमीरों से अधिक कर एकत्र करती है और इसे विभिन्न सरकारी–सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करती है। हमें यह भी समझना होगा कि समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर कम संसाधन वाले लोगों के उत्थान का महत्व न केवल सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तक देश के सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, हम भारत को कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। इतना ही नहीं, समाज में असमानताएं वैमनस्य को भी बढ़ावा देती हैं, जो सामाजिक ताने–बाने को बिगाड़ सकती हैं और विकास की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं। ❑❑

धुम्रपान और तंबाकू पर रोक का कोई असर नहीं

धुएं में बर्बाद होता भारत का भविष्य

भारत में धुम्रपान एक आम समस्या है। इसके साथ ही सूखा नशा लोगों को बुरी तरह जकड़ रहा है। यह एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बिगाड़ देती है। यह आदतें न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। नशे की गिरफ्त में आकर लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को नजरंदाज कर देते हैं और सामाजिक संबंधों में भी तनाव उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव से बचने के लिए शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है, साथ ही नशे के खिलाफ समाज में एक ठोस प्रयास करने की जरूरत है। केवल व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास ही इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों और सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अकेले राजधानी दिल्ली में ही कम से कम 20 फीसदी युवा इस तरह की चीजों के आदि हो चुके हैं। सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध के बावजूद इसको रोकने के लिए अभी तक की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। राजधानी दिल्ली में आम स्थानों के साथ–साथ अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्रों, हाई प्रोफाइल इलाके और एलीट जोनों, बड़े मार्केटों में यह उपलब्ध है। दिल्ली के कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, प्रेस क्लब, वीमेन प्रेस क्लब के साथ–साथ विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, सरकारी विभागों, राजनीतिक दलों के दफ्तरों के आसपास भी सूखे नशीले पदार्थ तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, हुक्का, चूरूट आदि खुलेआम स्ट्रीट वेन्डर्स, स्ट्रीट स्टॉल्स, स्ट्रीट मार्केट्स, कियोस्क्स, पॉप–अप शॉप्स पर मौजूद हैं। इस पर पूरी तरह से बैन नहीं लग पा रहा है। सरकार हर साल अधिसूचना जारी कर इस पर प्रतिबंध को आगे बढ़ा देती है। पिछला आदेश 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने जारी किया था।

इसको बैन करने को लेकर अप्रैल 2023 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने साफ तौर पर सरकार से पूछा था कि हर साल नई अधिसूचना

धुम्रपान को रोकने के लिए विकसित देशों में अपनाए गये विकल्पों पर विचार करना जरूरी है। इससे तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने में कारगर सफलता मिल सकती है।

–विक्रम उपाध्याय

गुटखा में तंबाकू की कितनी मात्रा हो, इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसको खाना अगर जरूरी ही है तो बिना तंबाकू वाले इसके फ्लेवर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं।

जारी करने के बजाय इस पर स्थायी रूप से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तब गुटखा निर्माताओं की ओर से कहा गया था कि सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी में ही इस पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उनका कहना था कि मौजूदा कानूनी ढांचे और लीगल फ्रेमवर्क में इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाना संभव नहीं है। इस पर रोक के लिए कानून बनाने में भी तमाम अड़चनें हैं।

इन तर्कों और दलीलों के चलते दिल्ली नशे के कारोबार का बड़ा केंद्र बन गया है। इसके पीछे नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता तथा गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव के चलते हो रहे डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलने जैसी बड़ी वजह भी है। इसके साथ ही मौजूदा पारिवारिक ढांचा और शिक्षा की कमी से हो रहे भटकाव तथा अज्ञानता भी नशे को बढ़ावा देने में मददगार बन रहा है। इसका सबसे बुरा असर हमारे कम उम्र के कालेज–गोइंग लड़के–लड़कियों पर पड़ रहा है। थोड़ी सी मस्ती, अति उत्साह और सामाजिक आचार–विचार के प्रति बेरुखी के चलते खुद को बिंदास, बेपरवाह दिखाने के लिए ड्रिंक्स, स्मोकिंग, च्युइंग एडिक्शन जैसी आदतें अपनाने को वह जरूरी मान बैठे हैं।

गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए मेडिकल जर्नल प्रकाशित करने वाले अभय प्रताप कहते हैं कि हर कोई जानता है कि नशा एक जहर है, लेकिन इस जहर के बदले जो थोड़ा सा मजा, आनंद और मनोरंजन मिलता है, उसे वह सोशल स्टेटस के लिए अतिजरूरी मान बैठे हैं। इसे छोड़ने के लिए वह कतई राजी नहीं हैं।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें हानिकारक सामग्री की मात्रा को कम या अलग–अलग करके नहीं बेचा जा रहा है। गुटखा में तंबाकू की कितनी मात्रा हो, इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसको खाना अगर जरूरी ही है तो बिना तंबाकू वाले इसके फ्लेवर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे इसको खाने का मजा तो आए, लेकिन स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़े।

दिल्ली में सूखे नशे में केवल तंबाकू या गुटखा ही नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तस्करी चोरी के जरिए बड़े पैमाने पर गांजा, हेरोइन, स्मैक, चरस, कोकेन, मेथिलीनडायऑक्सी–मेथाम्फेटामाइन (एमडीएमए) एक्स्टसी सिंथेटिक टैबलेट और पाउडर, मेफेड्रोन पाउडर और कैप्सूल तथा कोडीन मिला हुआ कफ सिरप को लाकर भी बेचा जा रहा है। नए जमाने में सुरक्षा के नाम पर ई–सिगरेट का भी प्रचलन बढ़ गया है। इसमें धुआं भले ही न हो, लेकिन निकोटीन होने से स्वास्थ्य के लिए नुकसान में जरा सी भी कमी नहीं है।

पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली में वरिष्ठ सलाहकार मेडिसिन डॉ. मोहसिन वली कहते हैं, "भारत में तंबाकू सेवन करने वालों, विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों की बढ़ती संख्या के चलते इस पर नियंत्रण के लिए बनाई गई नीतियों की तुरंत समीक्षा की जरूरत है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एनआरटी), गर्म तम्बाकू उत्पाद (एचटीपी) और स्नस (धुआं रहित तंबाकू) जैसे वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित विकल्पों के इस्तेमाल से नशे पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। हालांकि एनआरटी को मेडिकल स्टोर पर केवल डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर लिया जा सकता है। इसे सीधे कोई नहीं ले सकता है।"

बीएलके–मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट, पल्मोनरी मेडिसिन डॉ. पवन गुप्ता कहते हैं, "राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण – 5 (एनएफएचएस–5) में तम्बाकू सेवन का 27.3 प्रतिशत प्रचलन चिंताजनक है। लोगों में इसका प्रचलन बढ़ रहा हैं, क्योंकि देश भर में सड़क वाली दुकानों में तंबाकू आसानी से उपलब्ध है। मौजूदा सरकारी नीतियां इस आदत को रोकने और तंबाकू छोड़ने में प्रभावी रूप से सहायता करने में विफल रही हैं। कानून और नीतियों को बनाने वाली संस्थाओं को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसको रोकने के लिए विकसित देशों में अपनाए गये विकल्पों पर विचार करना जरूरी है। इससे तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने में कारगर सफलता मिल सकती है।" ❑❑

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी प्राकृतिक खेती

हाल ही में दो घटनाक्रम सामने आये जिनके बारे में मुझे लगता है कि हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। यदि हम कड़ी जोड़ सकें, तो एक वाकया उस आपदा का संकेत देता है जिसका इंतजार है, और दूसरा दुनिया जिस बड़े संकट का सामना कर रही है, उससे निपटने के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करता है, जिसके आने वाले वर्षों में और भी बदतर होने की संभावना है।

जबकि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रमुख गेहूं उत्पादक यूरोपीय देश फ्रांस में भारी और लगातार बारिश के कारण फसल को बड़ा नुकसान हुआ है, नीदरलैंड के एक पत्रकार ने मुझे लिखा है कि क्या मौसम में स्पष्ट परिवर्तन किसानों के लिए आर्थिक आपदा बनने जा रहा है। उसकी चिंता हॉलैंड में, जो कुछ वह देखती है, उससे पैदा होती है, जहां बारिश रुकी नहीं है, खेत पानी से लबालब हैं, परिणामस्वरूप खेतों में लगाई आलू की फसल सड़ रही है और सब्जियों के बीज उग नहीं रहे हैं।

इस बीच भारत अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में है। जैसे–जैसे सामान्य तापमान बढ़ता जा रहा है, आशंकाएं हैं कि क्या देश आने वाले वर्षों में अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा? कुछ वर्ष पहले गेहूं की कटाई के दौरान गर्मी ने कहर ढहाया था। उसके एक साल बाद, मानसून के मौसम में भी लगभग एक महीने तक बारिश नहीं हुई, धान की खड़ी फसल पर असर पड़ा। यह जानते हुए कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में खेल बिगाड़ सकता है, सरकार अति–जागरूक हो रही है, उसने कदम उठाए हैं। इनमें गेहूं और गैर–बासमती निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना यकीनी बनाने के लिए विभिन्न कृषि वस्तुओं पर स्टॉक सीमा भी लागू करना शामिल है।

जैसा कि डच पत्रकार कहती हैं कि जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी घटना बनने जा रही है जिसके कृषि पर बेहद बड़े प्रभाव होंगे। जबकि उद्योग इसे अपनी क्लाइमेट स्मार्ट प्रौद्योगिकी बेचने के लिए उपयुक्त अवसर के रूप में देखते हैं, जिसकी वे बीते कई साल से मार्केटिंग कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया ने जलवायु के असर झेलने में समर्थ

सघन खेती पद्धतियों के बजाय कृषि–पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की ओर रुख करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि द्वारा निभाई जा रही भूमिका कम हो जायेगी, जो जलवायु विघटन की दिशा में ले जायेगी।

– देविन्दर शर्मा

कृषि के लिए दृष्टिकोण, नीतियों और रणनीतियों पर विचार किया है।

मानवता के लिए गुलबेंकियन प्रतिष्ठित पुरस्कार इस बार दो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तकर्ताओं के साथ ही आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती यानी एपीसीएमएनएफ को प्रदान किया गया है। दरअसल, यह पुरस्कार उन जलवायु कार्यों और जलवायु समाधानों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है जो उम्मीद और संभावनाओं को प्रेरित करते हैं। पुरस्कार के तहत 1 मिलियन यूरो नकद प्रदान किये जाते हैं। बीते दिनों, रायथु साधिकार संस्था (आरवाईएसएस) के कार्यकारी उपाध्यक्ष विजय कुमार ने यह पुरस्कार पुर्तगाल के लिस्बन में एक शानदार समारोह में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के हाथों प्राप्त किया। एपीसीएनएफ को दुनिया भर से प्राप्त 181 नामांकनों में से चुना गया था।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको से लेकर एशिया में फिलींपींस तक, और अमेरिका के टेक्सास से लेकर भारत में महाराष्ट्र तक– दुनिया के विभिन्न भागों में कृषि कड़े जलवायु प्रभावों से दो–चार है। विगत में भी, कुछ भागों में अतिवृष्टि, बाढ़, भयंकर तूफानों व चक्रवातों की बढ़ती तादाद से कृषि को नुकसान पहुंचता रहा है तो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा और भीषण अकाल जैसी स्थितियां रही हैं। कहने की जरूरत नहीं कि जलवायु प्रेरित मौसम के मिजाज का खेती पर संचयी हानिकारक प्रभाव पड़ा है। जबकि किसान जलवायु का प्रकोप सहन करता है, वहीं नीति नियंता इसको नहीं मानते या इन विनाशकारी प्रभावों को कभी–कभार की घटनाओं के रूप में लेते हैं। यह ऐसा लगता है, जैसे दीर्घकाल तक चिंता करने की कोई बात ही नहीं हो।

जबकि सतत कृषि के बारे में बातें की जाती रही, कृषि–पारिस्थितिकीय खेती प्रणालियों पर पिछले कुछ सालों में ध्यान गया है। यहां लगता है कि आंध्र प्रदेश में प्रोत्साहित की गयी समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती प्रणालियां विश्व में कृषि–पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के रूप में सामने आयी है और परिणामस्वरूप सामने मौजूद बेहद हानिकारक जलवायु संकट का स्थाई समाधान प्रदान करती है। ऐसा भी महसूस होता है कि जलवायु संकट का यह जो कृषि–पारिस्थितिकीय समाधान प्रदान करती है वह उम्मीद और संकल्पों से भरपूर है। यह सही वक्त है कि क्षेत्र–विशेष की अनुकूलताओं को ध्यान में रखकर, आंध्र प्रदेश का यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाये। जैसा कि यह लेखक प्रायः कहते हैं कि जो 8 लाख किसान पूरी तरह से रासायनिक कृषि से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की ओर रुख कर चुके हैं या करने की प्रक्रिया में हैं, वे कड़ी चुनौतियों से दो–चार होते हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष आने वाली खरीफ और रबी सीज़न की रिपोर्टों में उजागर किया जा चुका है।

जब हरित क्रांति आयी, तो सघन कृषि पद्धतियों को अंजाम देने के लिए एक सुनियोजित और तय इको सिस्टम था। इसमें विश्वविद्यालयों, विशेष रिसर्च संस्थानों, कृषि विस्तार नेटवर्क, और कृषि ऋण तंत्र की स्थापना करने के साथ ही यथोचित विपणन अवसर पैदा करना शामिल था। जब भी जरूरी हुआ तो सब्सिडी व निवेश का प्रवाह भी रहा। इससे भी ज्यादा मदद के रूप में, बीज विकास संरचना का सृजन और उर्वरक संयंत्र और कीटनाशक कारखानों की स्थापना करना शामिल रहा।

प्राकृतिक कृषि के मामले में, हरित क्रांति को मदद देने के लिए जो विशाल सहायक प्रणाली निर्धारित की गई थी, उसका एक अंश भी प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि जलवायु मसले के समाधान करने को लेकर प्राकृतिक खेती ने अपनी भूमिका और क्षमता स्पष्ट तौर पर दर्शायी है। आने वाले समय के मुताबिक इसे इसकी उचित मान्यता दी जानी बाकी है। इसी प्रकार, दूसरे उन विभिन्न एग्रो–इकोलोजिकल दृष्टिकोणों को भी यथोचित मान्यता प्रदान की जानी जरूरी है जिनका प्रदर्शन देश के अलग–अलग इलाकों में प्रगतिशील किसान कर रहे हैं। सामूहिक तौर पर, माना जा सकता है कि अब वक्त आ गया है कि नीतिगत आयोजन में नॉन–कैमिकल दृष्टिकोणों को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की जाये।

पहली और सबसे महत्वपूर्ण कोशिश नौकरशाहों, न्यायाधीशों और कुलपतियों के लिए समय–समय पर ओरिएंटेशन आयोजित करने को एक तंत्र विकसित करने की होनी चाहिए। समाधान इसी में निहित है। इस मामले में महत्वपूर्ण उन लोगों की सोच को बदलना इतना आसान नहीं है जो उस माहौल में बड़े हुए हैं जहां कृषि रासायनिक साधनों के प्रयोग पर आधारित है। नये ढंग की कृषि की ओर उनका रुझान करने लिए जरूरत है एक निरंतर शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम की जो छोटी अवधि के कोर्सेज में विभाजित हो, जो खेती को भविष्य के लिये तैयार करे।

संक्षेप में, सघन खेती पद्धतियों के बजाय कृषि–पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की ओर रुख करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि द्वारा निभाई जा रही भूमिका कम हो जायेगी, जो जलवायु विघटन की दिशा में ले जायेगी। साथ ही इससे कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए शामक रणनीतियां बनायी जा सकेंगी। इसके साथ ही, तीसरा लाभ है यह लोगों के लिए स्वस्थ भोजन मुहैया कराएगी।❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।
https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/natural-farming-will-ensure-food-security/

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तनः भारत की चिंता

इसी माह 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को अभूतपूर्व जनाक्रोश, छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन, देश भर में अराजकता, हिंसा, सरकारी और निजी सम्पत्तियों को नष्ट करने और आंतरिक विद्रोह के कारण त्यागपत्र देकर भारत में शरण लेने को विवश होना पड़ा। आरक्षण विरोधी छात्रों का आंदोलन छद्म रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों का षड्यंत्र साबित हुआ। उनके सरकारी आवास में जमकर लूटपाट हुई। उनकी अवामी लीग पार्टी हाल ही में इसी वर्ष जनवरी 2024 में ही शेख हसीना के नेत्रत्व में विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बहिष्कार के बाद भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। शेख हसीना के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में बांग्लादेश ने एशिया में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में ख्याति प्राप्त की थी और विश्व के सभी बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने अपनी इंडस्ट्री बांग्लादेश में स्थापित की थीं। बांग्लादेश का सकल घरेलू उत्पाद भी 6 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा था और 1971 में पाकिस्तान से स्वतन्त्रता के बाद से यह देश आर्थिक स्थिति में बहुत आगे निकाल चुका था जहां पाकिस्तान की 1947 में स्वतन्त्रता के बाद 77 वर्ष बाद सकल घरेलू उत्पाद में (माइनस 2 प्रतिशत की) गिरावट है और वह विदेशी और घरेलू ऋण में डूबा है।

शेख हसीना के विरुद्ध आंदोलन के दौरान और उनके सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्ध और ईसायियों के विरुद्ध भारी हिंसा हो रही है। हिन्दू मंदिरों को जलाकर नष्ट करना, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्याएं लगातार हो रही हैं जो घोर चिंता का विषय है और जिसके विरोध में भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन, रैलियाँ हो रही हैं और केंद्र सरकार कर दवाब डाला जा रहा है कि वह बांग्लादेश में हिदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश में भी हिंदुओं ने आंदोलन किया है।

भारत के साथ बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल के साथ 4156 किमी लंबी सीमा पर शांति थी। ऐसा नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के बीच समस्याएँ नहीं हैं क्योंकि भारत में बंगलादेशी नागरिक और रोहिङ्ग्य मुसलमान बड़ी

आज की परिस्थिति में बांग्लादेश के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता परंतु यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश की पिछले पंद्रह वर्षों की स्थिरता और आर्थिक प्रगति इस्लामिक कट्टरपंथियों की भेंट चढ़ गई।

–विनोद जौहरी

मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद भी देश में अराजकता, लूटपाट, हिंसा कम नहीं हो रही। बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन को कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने त्यागपत्र देने को विवश कर दिया। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल राऊफ तालुकदार को भी त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार बांग्लादेश की न्यायपालिका और अर्थतंत्र देश में विदेशी षड्यंत्र द्वारा जनित अराजकता की भेंट चढ़ गए।

सख्या में वर्षों से घुसपैठ किए हुए हैं और अवैध रूप से उनके आधार, वोटर कार्ड, पैन आदि बन गए हैं और भारतीय जनमानस में उनके कारण जनसंख्या बदलाव को लेकर गंभीर चिंताएँ हैं। भारत सरकार भी बांग्लादेश में हिदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत के प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेस के सर्वोच्च नेता और संसद में विपक्षी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी पर भी बांग्लादेश मीडिया में शेख हसीना की सत्ता पलटने और देश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंसा, अराजकता फैलाने में विदेशी ताकतों का साथ देने एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के पुत्र तारीक़ रेहमान से लंदन में मिलने के आरोप हैं जिसका काँग्रेस की तरफ से खंडन नहीं हुआ। भारत के लोकतन्त्र में यह ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी राजनीतिक दल पर किसी अन्य देश के सत्ता पलट के विदेशी षड्यंत्र में संलिप्तता का आरोप लगा है।

शेख हसीना के त्यागपत्र के पश्चात देश को स्थिरता देने के लिए उनके सेना अध्यक्ष वकार उज जमा ने ज़िम्मेदारी ली। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया को नज़रबंदी से मुक्त किया और नोबल पुरुस्कार विजेता 84 वर्षीय मोहम्मद युनूस को पेरिस से बुलाकर उनके नेत्रत्व में अन्तरिम सरकार का गठन किया। ऐसा विश्वास दिलाया गया की मोहम्मद युनूस के नेत्रत्व में सरकार गठन के पश्चात देश में शांति स्थापित होगी और आम चुनाव के पश्चात देश फिर से प्रगति के मार्ग पर अग्रसारित होगा।

मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद भी देश में अराजकता, लूटपाट, हिंसा कम नहीं हो रही। उनके शपथ लेने के बाद बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन को कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने त्यागपत्र देने को विवश कर दिया। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल राऊफ तालुकदार को भी त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार बांग्लादेश की न्यायपालिका और अर्थतन्त्र देश में विदेशी षड्यंत्र द्वारा जनित अराजकता की भेंट चढ़ गए। अभी के समाचारों में बांग्लादेश की सेना पर भी हमलों के समाचार हैं। यह बिलकुल वैसा ही परिद्रश्य हैं जैसा पाकिस्तान में है जहां पूरा शासन तंत्र नष्ट भ्रष्ट है।

पदच्युत शेख हसीना ने सीधे अमेरिका पर बांग्लादेश में हस्तक्षेप और उनको सत्ता से उखाड़ने का आरोप लगाया है जिसके पीछे बांग्लादेश के एक द्वीप सैंट मार्टिन पर अमेरिकी सेना के अड्डे को स्थापित करने का प्रयास था। बांग्लादेश में एक सप्ताह में ही सब कुछ बादल गया और देश दीर्घकालिक अराजकता की भेंट चढ़ गया जो भारत की चिंता का विषय है। विदेशी षड्यंत्र की परतें खुल रही हैं और बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों का वर्चस्व स्थापित हो गया है।

बांग्लादेश में हिंसक सत्ता परिवर्तन का यह पहला घटनाक्रम नहीं है। बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। पूर्व राष्ट्रपति ज़िया उर रहमान की हत्या हुई। कितने ही विपक्षी नेताओं की हत्या हो चुकी है। इन घटनाक्रमों को दोहरने से आज की भयानक स्थिति का समाधान नहीं निकल सकता। यदि बांग्लादेश और अन्य विदेशी मीडिया और इस्लामिक देशों के मीडिया पर द्रष्टिपात करें तो शेख हसीन पर उनके 15 वर्षों के शासन में निरंकुशता, भ्रष्टाचार, विरोधियों के दमन, अपहरण, हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं और प्रमुख विरोधी नेताओं को जेलों में डाला गया है। शेख हसीना के सत्ता छोडने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया और नोबल पुरुस्कार विजेता एवं वर्तमान सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस भी जेल में थे और उनपर गंभीर आरोप थे। इन समाचारों से ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि बांग्लादेश में लोकतन्त्र निरंकुशता का पर्याय हो गया था। जब इस्लामिक कट्टरपंथी शासन अपने हाथों में ले लेते हैं तो विनाश कोई रोक नहीं सकता।

आज की परिस्थिति में बांग्लादेश के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता परंतु यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश की पिछले पंद्रह वर्षों की स्थिरता और आर्थिक प्रगति इस्लामिक कट्टरपंथियों की भेंट चढ़ गई। जिन विदेशी कंपनियों ने बांग्लादेश में अपनी इंडस्ट्री स्थापित की उनको भी इस पर आगे भविष्य के लिए विचार करना होगा। भारत को वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक पहल करने की आवश्यकता है। हाल की वैश्विक घटनाओं, सत्ता परिवर्तनों और विभिन्न देशों में विदेशी हस्तक्षेप से अराजकता और अस्थिरता से यह बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। ❑❑

पानी के लिए पर्याप्त प्रावधान है बजट में

भारत जनसंख्या बहुल और कृषि प्रधान देश है। इसलिए आम बजट की दृष्टि से जल संसाधन, पेयजल, ग्रामीण विकास और स्वच्छता ऊर्जा और परिवहन आदि ज्यादा महत्व के हो जाते हैं। जब एक केंद्रीय बजट आता है तब यह न केवल पैसे के आवंटन को सुनिश्चित करता है बल्कि सरकार के विजन और दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है। वर्ष 2024–25 के केंद्रीय बजट में पेयजल और स्वच्छता विभाग को 77390.68 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2023–24 के बजट में घोषित रकम के मुकाबले महज शून्य दशमलव पांच प्रतिशत अधिक है। दरअसल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए इस वित्त वर्ष के आवंटन का एक बड़ा हिस्सा जल जीवन मिशन की ओर निर्देशित है जिसे 69926. 65 करोड रुपए मिले जो वर्ष 2023–24 में 69846.31 करोड रुपए के संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक है।

जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण भारत के सभी घरों मेंव्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को भी लागू करेगा जैसे कि ग्रे–वॉटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन उपयोग। जल जीवन मिशन पानी के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना शिक्षा और संचार शामिल होंगे। जल जीवन मिशन पानी के लिए एकजुट आंदोलन बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है जिससे कि यह आम नागरिक के लिए प्राथमिकता बन जाए।

जल जीवन मिशन का प्रमुख उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देने का है। बजट में इसका प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया है इसके साथ–साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान को 95 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं जो पिछले संशोधित अनुमान में मिले 3 करोड रुपए से अधिक है।

इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो खुले में शौच मुक्त ऑडियो की स्थिति को बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने पर केंद्रित है के लिए 7192

जीवन के लिए जरूरी पानी हेतु मोदी सरकार के बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। जिन परियोजनाओं का काम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनमें तेजी लाने के लिए समानान्तर विभागों को जोड़कर काम में गति लाने का इंतजाम किया गया है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के अनुरूप और राष्ट्रव्यापी स्वच्छता प्रयासों को समर्थन देना जारी रखता है। बजट में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 64302. 85 करोड रुपए का महत्वपूर्ण वित्त पोषण भी शामिल है, जो पिछले वर्ष के 64138. 41 करोड रुपए से अधिक है।

आर्थिक सेवाओं के लिए बजट में सचिवालय के लिए 35.78 करोड रुपए और सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिवेश शामिल है। यह संशोधित बजट में 32.5 करोड रुपए से अधिक है जो प्रशासनिक और और संरचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। अतिरिक्त आवंटन में पूर्वोत्तर भारत के लिए 7632. 19 करोड रुपए शामिल है, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में जल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करना है। राज्य सरकारों को अनुदान सहायता 5169.86 करोड रुपए निर्धारित की गई है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान 250 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

सुरक्षित गुणवत्ता वाले पानी की पर्याप्त मात्रा एक मौलिक मानव अधिकार है, लेकिन भारत में अभी भी यह 100 प्रतिशत सुनिश्चित नहीं है। इसे प्राप्त करने, संग्रहित करने, उपयोग करने और प्रबंध करने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता होती है। जीवन को बनाए रखने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और राष्ट्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ जल तक पहुंच आवश्यक है। इसलिए बुनियादी मानवीय आवश्यकता की गारंटी देने अस्थाई जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने संसाधनों का अनुकूलन करने और इस महत्वपूर्ण संसाधन तक सामान्य आदमी की पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस तरह पानी मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, इसी तरह यह राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्र के अस्तित्व

बजट में जल शक्ति मंत्रालय को पर्याप्त आवंटन किया गया है। देश के कुल 19.26 करोड़ ग्रामीण घरों में से अब तक 14.22 करोड़ घरों को मिशन के तहत नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को पूर्व के बजट की तुलना में इस बार भी अधिक रकम दी गई है।

को आगे बढ़ाने वाली सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक है।

भारत में जल उपचार उद्योग पर्याप्त वृद्धि के चरण में है जिसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 9.10 प्रतिशत है जिसके 2030 तक 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 46480 करोड रुपए तक पहुंचाने का अनुमान है। इस वृद्धि का श्रेय विभिन्न सरकारी पहलों को जाता है, जिसमें अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफारमेशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल जीवन मिशन और सामुदायिक पेयजल योजनाएं शामिल है जो सामूहिक रूप से भारतीय जल और अपशिष्ट जल उपचार बाजार के विस्तार में योगदान करती हैं। मौजूदा बजट में विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है और कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता का जब शताब्दी वर्ष होगा यानी 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। सरकार ने बजट के जरिए विकसित भारत का एजेंडा सेट किया है।

बजट में जल शक्ति मंत्रालय को पर्याप्त आवंटन किया गया है। देश के कुल 19.26 करोड़ ग्रामीण घरों में से अब तक 14.22 करोड़ घरों को मिशन के तहत नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को पूर्व के बजट की तुलना में इस बार भी अधिक रकम दी गई है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने वाले विभाग के अंतर्गत आने वाली राशि गंगा योजना को दो प्रतिशत अधिक बजट आवंटित किया गया है, वहीं केंद्रीय जल आयोग को 392 करोड रुपए, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन को 78 करोड रुपए और केंद्रीय भूजल बोर्ड को 340 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2024–25 के बजट में 11391 करोड आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल से 29.7 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गठित 3.0 नई सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति सीवेज शोधन और ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं एवं सेवाओं को बढ़ावा देगी। लोकसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए शोधित जल के इस्तेमाल और आसपास के क्षेत्र में तालाबों को भरने की भी परिकल्पना की गई है।

कुल मिलाकर जीवन के लिए जरूरी पानी हेतु मोदी सरकार के बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। जिन परियोजनाओं का काम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनमें तेजी लाने के लिए समानान्तर विभागों को जोड़कर काम में गति लाने का इंतजाम किया गया है। साथ ही पानी पर हो रही वैश्विक बेइमानी को रोकने के लिए भी तंत्र विकसित करने की बात बजट में शामिल है। ❑❑

बैंकों में घटता चालू और बचत खाता अनुपात, चिंतन का विषय

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग आंकड़ों ने भारतीय बैंकों के चालू और बचत खाता (कासा) अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति को न केवल बैंकरों के लिए, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बना दिया है। कासा जमा राशि बैंकों के लिए धन की लागत निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कुल जमा के संबंध में कम लागत वाली जमा के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। लंबे समय से 40 प्रतिशत के कासा अनुपात को बैंकिंग उद्योग के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है। लेकिन हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग आंकड़ों से पता चलता है कि अखिल भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कासा अनुपात 31 मार्च 2024 को 40.97 प्रतिशत था जबकि यह अनुपात मार्च 2023 में 43.52 प्रतिशत और मार्च 2022 में 45.15 प्रतिशत था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी प्रकार के बैंकों, चाहे निजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र, में यह अनुपात समान रूप से नीचे चला जा रहा है। निजी क्षेत्र के बैंकों में यह अनुपात पिछले तीन वर्षों में 46.98 प्रतिशत से घटकर 40.64 प्रतिशत हो गया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनुपात 43.70 से घटकर 40.54 प्रतिशत हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कासा जमा राशि में कमी आई है। वास्तव में इसकी राशि मार्च 2022 में 76,80,341 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2023 में 81,56,674 करोड़ रुपये और अंततः 31 मार्च 2024 तक 87,08,940 करोड़ रुपये हो गई है।

आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2024 तक एसएसबी की सावधि जमा राशि भी बढ़कर 1,25,44,418 करोड़ रुपये हो गई है। मार्च 2023 में 1,05,85,637 करोड़ रुपये और मार्च 2022 में 93,28,455 करोड़ रुपये। इसका मतलब यह है कि जहां कासा पिछले दो वित्तीय वर्षों में 6.7 और 6.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है, वहीं सावधि जमा में पिछले दो वित्तीय वर्षों में 18.5 प्रतिशत और 13.47 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि सावधि जमा की वृद्धि दर कासा जमा की वृद्धि दर से आगे निकल गई

बैंकों ने सभी मापदंडों में सुधार दिखाया है, लेकिन अपने घटते कासा अनुपात को नियंत्रित करने में विफल रही, जिससे इसकी शुद्ध ब्याज आय पर असर पड़ा।

– विकास सिन्हा

है। इसका अभिप्राय यह निकाला जा सकता है कि ग्राहक सावधि जमा की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे है और अब वो अपना पैसा बचत या चालु खाता में कम और सावधि जमा में अधिक रखने को इच्छुक हैं। इसका मुख्य कारण हाल के वर्षों में सावधि जमा खातों में बढ़ते ब्याज को माना जा सकता है।

बैंकों द्वारा दी जाने वाली सावधि जमा पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत तक है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर 2.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत है। ब्याज की इस असमानता ने ग्राहकों को अपने राशि को सावधि जमा में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। रिज़र्व बैंक के आँकड़ों से निकलने वाला एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऋण वृद्धि ने जमा वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही में वर्ष–दर–वर्ष (वर्ष–दर–वर्ष) 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जमा राशि पर ऋण (सीडी) अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, मार्च 2024 तक 380 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर 79.7 प्रतिशत हो गया, जो उच्च ऋण वृद्धि और बैंकिंग क्षेत्र के भीतर विलय के प्रभावों से प्रेरित था। बाजार की बढ़ती ऋण मांग ने बैंकों को अपनी जमा दर को आकर्षक बनाने और परिसंपत्ति देनदारी का उचित मिश्रण बनाए रखने के लिए अपनी जमा दरों में वृद्धि करने के लिए मजबूर किया है।

वर्तमान में कासा अनुपात अपने बेंचमार्क के आसपास मंडरा रहा है और यदि ऋण उठाव में समान स्थिरता बनी रहती है और मौद्रिक नीति में कोई ढील नहीं होती है तो यह इस स्तर को तोड़ देगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य–संचालित बैंक अधिकारियों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कम लागत वाले संसाधन जुटाने के लिए रचनात्मक जमा तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है।

वर्तमान में कासा अनुपात अपने बेंचमार्क के आसपास मंडरा रहा है और यदि ऋण उठाव में समान स्थिरता बनी रहती है और मौद्रिक नीति में कोई ढील नहीं होती है तो यह इस स्तर को तोड़ देगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य-संचालित बैंक अधिकारियों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कम लागत वाले संसाधन जुटाने के लिए रचनात्मक जमा तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है।

कासा जमा राशि बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

बचत खाते के साथ ढ़ेर सारे लाभ की पेशकशः जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए बैंक बचत खातों पर कई तरह के लाभ दे सकते है। उदाहरण के लिए, कुछ बैंक ने वेतनभोगी जमाकर्ताओं को लक्षित करते हुए अभियान शुरू किया है, जिसमें 50 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, लॉकर किराये के शुल्क पर छूट, मुफ्त लॉकर संचालन, एक मुफ्त प्लैटिनम रुपे कार्ड जैसे लाभ दिए जा रहे हैं।

ग्रामीण भारत पर ज्यादा फोकसः यह पाया गया है कि ग्रामीण जमाकर्ताओं ने अपना जमा मिश्रण बरकरार रखा है, ग्रामीण जमाकर्ताओं के बीच जमा की अस्थिरता बहुत कम है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कासा डिपॉजिट बरकरार है, इसलिए बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

न्यूनतम शेष शुल्क की अवधारणा को समाप्त करनाः कासा खाते को बनाए रखने के लिए न्यूनतम शेष राशि या त्रैमासिक औसत शेष को समाप्त करने से अधिक खाते खोलने को बढ़ावा मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप कासा अनुपात बेहतर होगा।

सरकारी लाभार्थी खातों के लिए डिजिटल पहलः सरकारी लाभार्थी खातों को भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उनमें धन की स्थिरता होगी।

कासा खातों में सावधि जमा और चालू/बचत का मिश्रणः चूंकि ग्राहक म्यूचुअल फंड और अन्य उच्च उपज वाले उपकरणों की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए बैंक लचीले कासा खातों की पेशकश कर सकते हैं, जो किसी दिए गए शेष राशि के अलावा बेहतर ब्याज दर के साथ चालू/बचत के साथ–साथ अल्पकालिक जमा का मिश्रण भी प्रदान कर सकते हैं।

मौद्रिक नीति में ढ़ीलः हाल के वर्षों में आरबीआई ने अपनी रेपो दर को अपरिवर्तित और उच्च स्तर पर बनाए रखा है, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट और जमा पर उच्च ब्याज दर हो गई है।

रेपो दर में ढील के साथ क्रेडिट और जमा दर दोनों नीचे की ओर चले जाएंगे, जिससे सावधि जमा कम आकर्षक हो जाएंगे और अधिक धन का प्रवाह कासा खातों की तरफ होगा।

हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों ने अच्छा मुनाफा दिखाया है और उच्च लाभांश की घोषणा की है। बैंकों ने सभी मापदंडों में सुधार दिखाया है, लेकिन अपने घटते कासा अनुपात को नियंत्रित करने में विफल रही, जिससे इसकी शुद्ध ब्याज आय पर असर पड़ा। आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए बैंकों की ओर से शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। ❑❑

लेखक पंजाब नेशनल बैंक (दिल्ली) के मुख्य प्रबंधक है।

स्वदेशी जागरण मंच

राष्ट्रीय परिषद बैठक

28, 29, 30 जून, 2024 (लखनऊ–अयोध्या, उ.प्र.)

नये दायित्व

क्षेत्रीय दायित्व

1. दक्षिण मध्य क्षेत्र

- श्री मंजूनाथ – क्षेत्र समन्वयक (पहले– क्षेत्र संयोजक)
- डॉ. एस. लिंगामूर्ति – क्षेत्र संयोजक (पहले– क्षेत्र सहसंयोजक)

2. पश्चिम क्षेत्र

- श्री हसमुख भाई ठाकर – गुजरात व सौराष्ट्र के संयुक्त संयोजक (पहले– गुजरात प्रांत संयोजक)

3. उत्तर क्षेत्र

- श्री सतेन्द्र सरोत – क्षेत्रीय सहसंयोजक (पहले– क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख)
- श्री विकास चौधरी – क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख (पहले– दिल्ली प्रांत संयोजक)

4. पूर्वी क्षेत्र

- श्री आशुतोष मुखर्जी – क्षेत्र संयोजक (पहले– ओडिशा प्रांत संयोजक)

5. असम क्षेत्र

- श्री अमल वैश्य – क्षेत्र संपर्क प्रमुख (पहले– राष्ट्रीय परिषद सदस्य)
- श्री रवि पटवा – क्षेत्र कोष प्रमुख (पहले– दक्षिण असम प्रांत संयोजक)

प्रांतीय दायित्व

1. दक्षिण कर्नाटक

- श्री जयवर्धन – प्रांत सह संयोजक (पहले– प्रांत सह विचार विभाग प्रमुख)

2. तेलंगाना

- श्री गौरी रमेश – प्रांत समन्वयक (पहले– प्रांत सह समन्वयक)
- श्री इंद्रसेन रेड्डी – प्रांत सह समन्वयक (पहले– हैदराबाद एसबीए केंद्र प्रमुख)

3. गुजरात

- श्री किरन सिंह गौर – प्रांत संयोजक (पहले– प्रांत सह संयोजक)
- श्री उदय भाई त्रिवेदी – प्रांत विचार विभाग प्रमुख
- श्री मनसुख भाई पटेल – प्रांत सह संयोजक (पहले– विभाग संयोजक)
- डॉ. सत्यजीत देशपांडे – प्रांत सह संयोजक (पहले– प्रांत विचार विभाग प्रमुख)
- डॉ. रत्ना बेन त्रिवेदी – दायित्व मुक्त (पहले– प्रांत सह समन्वयक)
- श्री पराग शाह – दायित्व मुक्त (पहले– प्रांत समन्वयक)

4. सौराष्ट्र

- श्री यशभाई जयसानी – प्रांत संयोजक (पहले– प्रांत सह संयोजक)

- श्री अमीश भाई हीरापुरा – प्रांत सह संयोजक (पहले– विभाग सह संयोजक)

5. जयपुर

- श्री सुरेंद्र कुमार नामा – प्रांत संयोजक (पहले– प्रांत सह संयोजक)
- श्री विनोद पाल यादव – प्रांत सह संयोजक (पहले– विभाग संयोजक)
- श्री दिनेश शर्मा – प्रांत सह समन्वयक (एसबीए)
- श्रीमति रीना जोशी – महिला प्रांत सह समन्वयक (एसबीए)

6. जोधपुर

- डॉ. महेश श्रीमाली – प्रांत सह समन्वयक (एसबीए)

7. जम्मू–कश्मीर

- श्रीमति अनीता शर्मा – प्रांत महिला प्रमुख (पहले– महानगर महिला प्रमुख)
- श्रीमति दीपाली अरोरा – प्रांत सह महिला प्रमुख

8. हिमाचल प्रदेश

- श्री सुनील – प्रांत सह संयोजक (पहले– विभाग संयोजक)

9. हरियाणा

- डॉ. भगत सिंह – प्रांत संपर्क प्रमुख (पहले– प्रांत सह समन्वयक)
- श्री दुलीचंद कालीरमन – प्रांत सह समन्वयक
- डॉ. नवीन जैन – प्रांत सह समन्वयक

10. दिल्ली

- श्री मनोज गुप्ता – प्रांत संयोजक

11. ब्रज प्रांत

- श्रीमति इंदु वाशनेय – स्वदेशी शोध संस्थान (पहले– प्रांत महिला प्रमुख)
- डॉ. रेणु दुबे – प्रांत महिला प्रमुख

12. गोरक्ष प्रांत

- श्री शैलेन्द्र राव – प्रांत सह संयोजक (पहले– प्रांत समन्वयक)
- श्री ईश्वर चन्द्र – प्रांत समन्वयक

13. काशी प्रांत

- श्री सतेन्द्र त्रिपाठी – केंद्रीय शोध संस्थान की कोर टीम के सदस्य तथा लिगल, संपर्क आदि कार्य देखेंगे। (पहले– प्रांत सह संयोजक)
- श्री अजय आनंद – प्रांत सह संयोजक (पहले– प्रांत सह समन्वयक)

14. कानपुर

- श्री सुदीप खरे – प्रांत सह संयोजक (पहले– प्रांत संघर्ष वाहिनी प्रमुख)

15. ओडिशा (पूर्व)

- श्री निर्मल षडंगी – प्रांत संयोजक (पहले– प्रांत सह संयोजक)
- श्री प्रसन्न छोटराय – प्रांत सह संयोजक (पहले– प्रांत विचार विभाग प्रमुख)
- श्री शत्रुघ्न तरई – राष्ट्रीय परिषद सदस्य (पहले– पूर्वी क्षेत्र संयोजक)

16. दक्षिण बंग प्रांत

- श्री अशोक पाल चौधरी – प्रांतीय टीम के सदस्य (पहले– प्रांत सह संयोजक)
- श्री नारायण पांडा – प्रांत सह संयोजक
- श्रीमति सुमन श्रीवास्तव – प्रांत महिला प्रमुख
- श्री सोमोरेश नसकर – पूर्णकालिक, दक्षिण बंग (पहले– पूर्णकालिक, उत्तर बंग)
- श्री अर्घ्य बनर्जी – प्रांत सह समन्वयक (एसबीए)

17. मध्य बंग

- श्रीमति बानी सरकार – प्रांत महिला प्रमुख (पहले– प्रांत सह संयोजक)
- श्री विश्वजीत दास – प्रांत सह संयोजक (पहले– प्रांत संपर्क प्रमुख)
- श्री शंकर मेहता – प्रांत समन्वयक (एसबीए)

18. उत्तर बंग

- श्री पार्थ दास – प्रांतीय टीम सदस्य (पहले– प्रांत सह संयोजक)

19. दक्षिण असम

- प्रो. जयदीप भट्टाचार्य – प्रांत संयोजक (पहले– प्रांत विचार विभाग प्रमुख)

20. त्रिपुरा

- श्री सुब्रत नंदी – प्रांत सह संयोजक

21. अरूणाचल प्रदेश

- प्रो. कमलेश – प्रांत संयोजक

22. मणिपुर

- श्री रोशनी कुमार – प्रांत सह संयोजक

उद्यमिता से उज्जवल भविष्य की ओर भारत : कश्मीरी लाल

जैविक उद्यमिता आधारित स्वरोज़गार के मॉडल से भारत के युवाओं को एक नयी दिशा प्राप्त हो सकती है। उक्त बातें स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने स्वदेशी जागरण मंच, जम्मू कश्मीर प्रांत के दो दिवसीय विचार वर्ग के शुभारंभ करते हुए कही।

उन्होंने तमिलनाडु के शिवकाशी के उद्यमी श्नमुगम का उदाहरण देते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उधमपुर स्थित कलहाडी फैक्ट्री के शुभम् शर्मा को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। ऐसे ही अचार बनाने से जुड़ी युवा महिला उद्यमी प्रतीक्षा ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि उन्होंने कितनी ही बहनों को इस प्रकल्प में सम्मिलित किया हुआ है और रोज़गार प्रदान कर रही है। डायरेक्टर हैंडिक्राफ़्ट्स जम्मू श्री सूरज रक्कवाल ने उद्यमियों के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी।

मंच ने आह्वान किया कि लोग इस मानसिकता को बदलें कि नौकरी ही रोजगार है। देश में कुल 8 से 9 प्रतिशत ही सरकारी नौकरी है। युवा इस चुनौती का समाधान स्वयं का उद्यम–रोजगार, स्टार्टअप्स के माध्यम से कर सकते हैं।

मंच के उत्तर क्षेत्रीय अधिकारी प्रो. आशुतोष, मंच के पंजाब प्रांत संगठक विनय, प्रांत संयोजक विपिन, सह संयोजक डा. मुनीश, महानगर संगठक सुनील, प्रांत अधिकारी अजय चंदेल, विजय जौहर, यशदेव, महानगर संयोजक रवि; सह संयोजक नरेश आदि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रांत महिला प्रमुख अनीता और सह प्रमुख दीपाली भी दो दिवसीय कार्यशाला में सम्मिलित हुई।

https://www.khabarsangwari.com/2024/07/73737_27.html

उद्यमिता ही हमें शून्य से शिखर तक ले जायेगीः श्री कश्मीरी लाल

काजरी सभागार में स्वदेशी जागरण मंच जोधपुर प्रांत की दो दिवसीय विचार–वर्ग एवं कार्यशाला का आयोजन स्वालंबी भारत अभियान के तहत हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंच के राष्ट्रीय संगठन के श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि स्वदेशी की भावना घर से प्रारंभ होनी चाहिए, जब भी हम बाजार जाये तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्वदेशी सामान ही खरीदे। उद्यमिता के लिए धन से ज्यादा साहस और मेहनत की आवश्यकता होती है। आज मंच देश के 165 विश्वविद्यालय, 5000 से ज्यादा कॉलेज और 10 लाख स्टूडेंट तक स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा जनता तक जैविक उद्यमता का मंच सजा रहा है। शुभारंभ सत्र के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर प्रांत के संचालक हरदयाल वर्मा ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत कृषि और उद्योग में अग्रणी देश रहा है, लेकिन पश्चिमी कुटिल शक्तियों के चुंगल में फस जाने के कारण हमने अपनी उद्यमता को नष्ट कर दिया। नौकरी की चाह के कारण ही आज पढ़े–लिखे युवाओं में सर्वाधिक बेरोजगारी है। उद्योग मंत्री केके विश्नोई ने कहा कि स्वावलंबी भारत अभियान आज की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा भी युवाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, युवा अपना स्किल का विकास कर इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं।

शुभारंभ–सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर के वरिष्ठ उद्यमी पप्पूराम डारा ने कहा कि आज स्वालंबी भारत अभियान की अत्यंत आवश्यकता है, इसके द्वारा कौशल विकास सरकारी योजनाएं और सहकार द्वारा हम स्वरोजगार युवाओं को प्रदान कर सकते हैं। 2047 तक हमने जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत संरक्षक और वरिष्ठ उद्यमी राधेश्याम रंगा ने कहा कि आज का युवा नशे की ओर जा रहा है और उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। चीन की पॉलिसीयों के कारण हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि वह युवा उद्योगों को प्रोत्साहन दे, नीतियों को उद्यमता के अनुकूल बनाएं, जिससे अधिकाधिक युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त हो सके। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह– संयोजक डॉ राजकुमार मित्तल द्वारा लिखी पुस्तक 37 करोड़ स्टार्टअप्स का देश का विमोचन मंच के अतिथियों द्वारा किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के राजस्थान क्षेत्र के विचार प्रमुख डॉक्टर अनिल वर्मा ने पुस्तक का परिचय बताया। मंच का संचालन डॉ महेश श्रीमाली और प्रोफेसर कृष्ण अवतार गोयल ने किया। अतिथियों का स्वागत व परिचय प्रांत संयोजक प्रमोद पालीवाल ने दिया।

कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कृषि प्रमुख भागीरथ चौधरी, अखिल भारतीय सह–समन्वयक अर्चना मीणा, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र दुबे, भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष डालाराम चौधरी, सहकार भारती के प्रांत सह प्रमुख कमलेश गहलोत, जाने–माने सीए विशाल

बूब, अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख दीपक शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से डॉ हीरालाल, लघु उद्योग भारती से मंजू सारस्वत, भाजपा के उपाध्यक्ष जगराम विश्नोई, रमेश विश्नोई, प्रहलाद, कृषि वैज्ञानिक डी कुमार, ग्राहक पंचायत से धर्मेंद्र सोनी, तुलसाराम सीवर, महेश जांगिड़, बलवीर चौधरी, जय गोपाल पुरोहित, रमेश सोनी प्रांत प्रचार प्रमुख मिथिलेश झा, रमेश सोनी, महेश वैष्णव, महानगर संयोजक अमन भंडारी, संतोष मेहरा, प्रियंका त्यागी, राजेंद्र मेहरा, जितेंद्र मेहरा, प्रेम पालीवाल, सवाई कुमावत, देवकिशन, खेतुलाल, दिनेश, मुकेश शर्मा, विकास खिलेरी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

लोकल फॉर वोकल हीं राष्ट्र की उन्नति का आधारः डॉ. महाजन

स्वदेशी जागरण मंच का ब्रज प्रांतीय अभ्यास एवं प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता अखिल भारतीय सह सयोजक व भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री डा. अश्वनी महाजन ने कहा कि भारत को विकसित होने से कोई नही रोक सकता, और स्वदेशी व स्वावलंबन हीं इसका मुख्य आधार है। लोकल फॉर वोकल का मंत्र साकार हो रहा है और वर्तमान सरकार का बजट रोजगार बढ़ाने में सहायक होगा। आज भारत दुनिया का प्रमुख निर्यातक बन गया है। चीन को चुनौती देने में भारत आज पूरी तरह सक्षम है। उद्घाटन सत्र में अखिल भारतीय विचार प्रमुख डॉ. राजीव कुमार व क्षेत्र सयोजक श्री अमितेश अमित ने स्वदेशी की विकास यात्रा को प्रस्तुत किया।

मंच पर मुख्य अतिथि अपैक्स के मालिक श्री दुर्गेश गुप्ता ने स्ववदेशी का अर्थ समझाया। डॉ. पी.पी. सिंह, नगर संघचालक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन प्रांत सह सयोजक श्री मनोज अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के नियंत्रक श्री ऋषि बंसल, प्रांत सयोजक स्वावलंबी भारत अभियान रहे। प्रांतीय वर्ग में 12 जिलों के 87 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हाथरस से डा राधेश्याम वार्ष्णेय, डा देवेन्द्र शर्मा, अजय राघव, प्रभुदयाल कुशवाह, अनुपम गुप्ता, शालिनी अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बनेंः सतीश कुमार

जालंधर में 20–21 जुलाई को सम्पन्न हुए स्वदेशी जागरण मंच, पंजाब के दो दिवसीय प्रांत विचार वर्ग को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संगठक श्री सतीश कुमार ने युवाओं को आह्वान किया कि वे इस परिभाषा को बदलें कि नौकरी ही रोजगार है। देश में कुल 8 से 9 प्रतिशत ही सरकारी नौकरी है। युवा इस परिभाषा को बदलते हुए स्वयं का उद्यम–रोजगार, स्टार्टअप्स शुरू करें। जिससे कि वह भी आर्थिक प्रगति पर बढ़े और देश को भी इसका लाभ हो। वह "नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला" बने।

उन्होंने कहा कि यह बात ठीक है कि नौकरी आपको भूखे नहीं मरने देती, परन्तु यह बात भी सत्य है कि नौकरी आपको आगे भी बढ़ने नहीं देती। बड़ी संख्या में लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है।

आज युवाओं के लिए गुणवत्ता और उत्तमता वाली जिंदगी गुजारने के लिए यह जरूरी है कि वह अपना कोई नया उद्यम शुरू करें। जिससे समाज और लोगों का भी भला हो। पंजाब में विभिन्न आंदोलनों के कारण आर्थिक सामाजिक स्थिति जो खराब हो रही है उसको ठीक करने का मार्ग भी यही है की यहां के युवाओं को उद्यमिता के मार्ग पर लाने हेतु एक व्यापक जन जागरण किया जाए। इस अवसर पर डा. गुरबीर सिंह गिल, जिले के सबसे बड़े किसान सरदार रणतेज सिंह, आईआरएस गिरीश बाली, पंजाब के संगठक श्री विनय व अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

गांव–गांव तक स्वरोजगार के नए अवसर पहुंचाना लक्ष्यः दीपक शर्मा

स्वदेशी जागरण मंच, जमशेदपुर महानगर का जिला सम्मेलन तुलसी भवन में आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' एवं विशिष्ट अतिथि मंच के क्षेत्रीय संयोजक श्री अमरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का उद्घाटन भारत माँ के समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर के हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने कहा कि भारत का इतिहास 70 हजार वर्ष पूर्व का है और भारत ने पूरी दुनिया को ज्ञान, उद्योग, जीवन दर्शन, अध्यात्म योग और विकास का रास्ता दिया। स्वरोजगार के विषय पर स्वदेशी जागरण मंच का यह नारा है कि 'आगे चले समाज – साथ दे सरकार'। हमारा लक्ष्य गांव– गांव तक स्वरोजगार के नए अवसर को पहुंचाना है। अगले 5 वर्षों में हम पूरे विश्व को 1000 वर्षों का विकास का मॉडल बना कर देंगे। मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ राज कुमार मित्तल द्वारा रचित जैविक उद्यमिता पर आधारित '37 करोड़ स्टार्टअप का देश' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। सत्र में स्वावलंबी भारत अभियान को विस्तार से मंच के क्षेत्रीय संयोजक श्री अमरेंद्र कुमार सिंह ने रखा। उद्घाटन सत्र में विषय प्रवेश प्रान्त के सह प्रचार प्रमुख श्री अमित मिश्रा, स्वागत भाषण विभाग संयोजक श्री राजकुमार साह, संचालन प्रान्त के युवा प्रकोष्ठ श्री पंकज सिंह और धन्यवाद ज्ञापन जिला संयोजिका राजपति देवी ने दिया।

कार्यक्रम में मधुलिका मेहता, मंजू ठाकुर, अनिल राय, केपी चौधरी, जेकेएम राजू, संजीत प्रमाणिक, मुकेश ठाकुर, विकास साहनी, मुकेश भदानी, मनोज गुप्ता, श्याम दास, गुरजीत सिंह, अभिषेक बजाज, सत्यनारायण, गौरव, दुर्गा समेत सैकड़ों स्वदेशी समर्थक उपस्थित रहे।

'स्वदेशी जागरण मंच ने की सभी के हितों की रक्षा'

स्वदेशी जागरण मंच, टोंक के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. रजकुमार मित्तल की पुस्तक 'जैविक उद्यमिता 37 करोड़ स्टार्ट अप का देश' का विमोचन स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक श्री सुरेन्द्र नामा, श्री लोकेन्द्र सिंह नरूका, प्रांत सहसंयोजक एवं प्रांत समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान जयपुर प्रांत की ओर से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गोविन्द शरण गुप्ता, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी ने की। प्रांत संयोजक श्री सुरेन्द्र नामा ने कहा कि स्वदेशी की विकास यात्रा का लंबा इतिहास रहा है। स्वदेशी जागरण मंच देश में अनेक स्तरों पर संघर्ष किया। किसानों, मजदूरों, व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हुए उनके हितों की रक्षा की है। वर्तमान में देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार की है। जिसे युवा स्वयं का कार्य व्यवसाय प्रारंभ कर स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक लोकेन्द्रसिंह ने कार्यकर्ताओं को इस पुस्तक की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि युवा जैविक उद्यमिता अपनाकर स्वयं स्वावलंबी बन सकते हैं।

इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में भी स्वदेशी जागरण की वर्षों से चली आ रही मांग ईएलआई (एम्प्लॉयमेंट लिंक इन्सेंटिव) रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा की गई। युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए देश के बजट में 1.48 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया है। जिला संयोजक श्री देवेन्द्र खंडेलवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। सफल उद्यमी संजय संघी का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में चंद्रप्रकाश कुर्मी, अशोक कुमार जैन, विष्णु दत्त शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता उपस्थित थे।

युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगारोन्मुखी है बजटः स्वजामं

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा काफी समय से की जा रही ईएलआइ (एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव) रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम लायी जाए, जिसे इस बजट में स्वीकार करते हुए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई से संबंधित कई घोषणाएं की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय बजट 2024 पर देश के प्रमुख आर्थिक संगठनों में से एक स्वदेशी जागरण मंच जयपुर प्रांत द्वारा बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। बजट 2024 पर अपना मत रखते हुए प्रांत संयोजक सुरेन्द्र नामा ने कहा कि सरकार ने इस बजट में स्वदेशी जागरण मंच की मांग को स्वीकार करते हुए युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी के समाधान के लिए रोजगार और कौशल विकास के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। शिक्षा, रोजगार और

कौशल विकास के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो निसन्देह युवाओं, महिला ओ में स्वावलंबन तथा स्व–रोजगार की अवधारणा को पुष्ट करेगा।

प्रांत सहसंयोजक एवं स्वावलंबी भारत अभियान के समन्वयक लोकेन्द्रसिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, सर्व समावेशी मानव संसाधन विकास नवाचार, अनुसंधान विकास तथा उर्जा सुरक्षा पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए अगले 5 वर्षो में लगभग 11,11,111 करोड़ का वित्तीय प्रावधान, जो कि जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, सराहनीय है। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अवसरंचना निर्माण में सहयोग होगा बल्कि देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध होंगे।

प्रांत उप कोष प्रमुख सीए राजेश कन्दोई ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट में कौशल प्रशिक्षण के लिए संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक की ऋण सुविधा उपलब्ध होने से प्रतिवर्ष लगभग 25000 छात्रों को सहायता मिलेगी, जो स्व–रोजगार के माध्यम से वे स्वालंबन को प्राप्त करेंगे। बजट में विभिन्न कौशल विकास की योजनाओं से शिल्पकार, कारीगर, स्वयं सहायता समूह, स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री विश्व कर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के जो प्रस्ताव है, वह सराहनीय है। प्रांत प्रचार प्रमुख धर्मवीर चंदेल ने जनजातीय समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए देशभर के 63000 गांवों में रहने वाले 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लंबे समय से देश की आर्थिक समृद्धि में भागीदारी से वंचित जनजातीय समुदाय अपने कौशल का सदुपयोग करते हुए देश में अपना योगदान सुनिश्चित करेगा। क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुदेश सैनी ने चर्चा में बताया कि उधमिता तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिन उद्यमियों ने पूर्व में प्राप्त 10 लाख के मुद्रा ऋण को चुका दिया है, उनके मुद्रा ऋण की सीमा को 20 लाख कर दिया है, इससे निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने वाले युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उन्हें कार्य विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

प्रांत सहविचार विभाग प्रमुख एवं सहसंयोजक विनोद पाल यादव ने बताया कि बजट में शहरी क्षेत्र के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने, देश में ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण विकास, रोजगार के बीच में संतुलन पैदा करने हेतु नीतिगत दस्तावेज तैयार करने का स्वदेशी जागरण मंच स्वागत करता है। देश में पूंजी निर्माण की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। आंतकवाद पर रोक, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास, सड़क निर्माण, कृषि उत्पादन भंडारण तथा कैपिटल इनकम बढ़ाने में सहयोगी होगा। इस बजट चर्चा में प्रांत के सह समन्वयक दिनेश शर्मा, गुरेंन्द्र नाथ, देवेन्द्र खंडेलवाल, अशोक जैन सहित प्रांत, विभाग एवं जिले के दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है।

संतुलित बजट में सबके विकास की बातः डा. राजीव कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में एमडीए स्थित टैली अकैडमी में बजट पर चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं प्रदीप शर्मा द्वारा स्वदेशी गीत से हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डा. राजीव कुमार ने बजट पर विचार रखते हुए कहा कि बजट संतुलित हैं और भारत के विकास का खाका खींचता है। सभी के लिए बजट में कुछ ना कुछ है।

मुख्य वक्ता टैली इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सीए डा. अभिनव अग्रवाल ने टैक्सेशन पर विचार रखते हुए कहा कि भारत में 140 करोड़ में से मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं जिसमें से एक करोड़ से अधिक इनकम बताने वाले मात्र 97 हजार हैं। जिससे साफ है की लोग इनकम टैक्स अपनी इनकम कम दर्शाते हैं। सरकार को टैक्स का दायरा बढ़ाना होगा अन्यथा वेतन भोगी लोग ही पिसते रहेंगे।

प्रांत संयोजक कपिल नारंग प्रांत सह संपर्क प्रमुख डा एके अग्रवाल, महिला सह महानगर प्रमुख नीलम जैन आदि ने संबोधित किया। सीए हिमांशु मेहरा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विभाग संयोजक प्रशांत शर्मा एवं संयोजन महानगर महिला प्रमुख मीनू अरोड़ा ने किया। कार्यक्रम में डा. राजेश अग्रवाल, सीए आदित्य एवं इंस्टिट्यूट के छात्र–छात्रा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ❑❑

प्रांतीय प्रशिक्षण व विचार वर्ग

सचित्र झलक

जोधपुर

काशी

तेलंगाना

पूर्णकालिक बैठक, भोपाल (म.प्र.)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अगस्त 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांतीय प्रशिक्षण व विचार वर्ग

सचित्र झलक

जम्मू-कश्मीर

ब्रज प्रांत

जालंधर, पंजाब

झारखंड

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती